

रायपुर/बिलासपुर । यात्रियों की सुविधा, बेहतर रेल कनेक्टिविटी एवं सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 18249/18250 तथा 18251/18252 हसदेव एक्सप्रेस की सेवाओं का विलय कर इसे प्रतिदिन नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 18249/18250 रायपुर–कोरबा–रायपुर हसदेव एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन तथा 18251/18252 रायपुर–कोरबा–रायपुर हसदेव एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन संचालित की जा रही है। इन दोनों ट्रेनों की सेवाओं का विलय करते हुये 1 अगस्त से ट्रेन संख्या 18249/18250 कोरबा–रायपुर–कोरबा हसदेव एक्सप्रेस के रूप में प्रतिदिन संचालित होगी। इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यात्रियों को अब दो अलग–अलग ट्रेन नंबरों और अलग–अलग संचालन दिनों की जानकारी याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही ट्रेन संख्या 18249/18250 हसदेव एक्सप्रेस प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी, जिससे यात्रा योजना बनाना अधिक सरल और सुविधाजनक होगा। इस ट्रेन में कुल 15 आधुनिक एलएचबी कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

पहली से 12वीं तक की तिमाही-अर्धवार्षिक परीक्षाएं एक साथ होगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य के सभी स्कूलें 1 अप्रैल से खुल जाएंगी और इसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अभी से इसकी तैयारी शुरु कर दी है। इस सत्र से सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 12वीं तक की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक ही तारीख और एक साथ आयोजित होंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा की समय–सारणी और दिशा–निर्देश जारी कर दिए हैं। कक्षा पहला से आठवीं तक तिमाही परीक्षा 21 से 26 सितंबर व अर्धवार्षिक परीक्षाएं 1 से 7 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित होंगी। कक्षा 9 से 12वीं तक की तिमाही परीक्षा 21 से30 सितंबर व अर्धवार्षिक परीक्षाएं 1 से 11 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक आयोजित की जाएंगी। पहले जिलों में स्थानीय स्तर पर अलग–अलग तारीखों में परीक्षाएं होती थीं, लेकिन अब सभी जिलों में एक समान तिथि पर परीक्षा होगी। परीक्षा के संचालन और प्रश्नपत्र तैयार कराने के लिए हर जिले में जिला स्तरीय परीक्षा समिति बनाई जाएगी। समिति विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से गोपनीय प्रश्नपत्र तैयार करेगी और परीक्षा शुरु होने से दो दिन पहले विकासखंड व संकुल स्तर पर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराएंगी।

रायपुर की श्वेता सिंह को डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली

रायपुर। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर की छात्रा श्वेता सिंह को शिक्षण एवं साहित्य कार्यों को देखते हुए मानद उपाधि के रूप में विद्या वाचस्पति (डॉक्टरेट) की उपाधि अलंकार से सम्मानित किया गया है। शिक्षण कार्य एवं साहित्य सृजन क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के आधार पर किए गए शोध कार्यों को देखते हुए श्वेता सिंह को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान की उपाधि प्रसिद्ध दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित कर होटल रेडिसन ब्लू में दिया गया। रायपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि श्वेता सिंह को यह सम्मान शिक्षण एवं साहित्य कार्यों में किए गए शोध के लिए इस अलंकरण उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पदम् डॉक्टर अरविंद कुमार पूर्व कुलपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी,मुख्य अतिथि हरि भाई आर्यन ख्याति प्राप्त योग गुरु एवं समाजसेविका रूरति कृति सिंह सहित कई साहित्यकार और गण्यमान्य नागरिक मौजूद रहे।

भाजपा पार्षद के बेटे पर एफआईआर दर्ज निगम कर्मों से मारपीट का आरोप

रायपुर। नगर निगम के जोन क्रमांक-4 में पदस्थ जोन आयुक्त के वाहन चालक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। चालक की शिकायत पर जोन अध्यक्ष और भाजपा पार्षद मुरली शर्मा के बेटे अनिल शर्मा के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने सहित अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ देर के लिए जोन में कर्मचारियों ने काम भी बंद कर दिया था। बात निगम मुख्यालय तक भी पहुंच गई थी और सारे कर्मचारी लामबंद होने लगे थे कि पुलिस में एफआईआर हो जाने के बाद वे वापस काम पर लौटे। शिकायतकर्ता योगेन्द्र साहू (26), निवासी मठपुरैना ने पुलिस को बताया कि वह जोन क्रमांक-4 में जोन आयुक्त दिव्या चन्द्रवंशी के वाहन चालक हैं। योगेन्द्र के अनुसार, 30 जुलाई को अनिल शर्मा ने उन्हें नगर निगम कार्यालय बुलाया। वहां पहुंचते ही उसने कथित तौर पर कहा, तू ही मैडम का ड्राइवर है ? और गाली-गलौज शुरू कर दी। शिकायत में आरोप है कि विरोध करने पर अनिल शर्मा ने जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इस घटना में योगेन्द्र के सिर और कलाई में चोट आई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने जोन आयुक्त दिव्या चन्द्रवंशी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और गाली-गलौज की। हालांकि इस मामले में जोन कमिश्नर दिव्य चंद्रवंशी व जोन अध्यक्ष मुरली शर्मा ने कुछ भी नहीं कहा है। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर अनिल शर्मा के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में विकसित होगी आधुनिक विज्ञान अधोसंरचना

22वें अखिल भारतीय विज्ञान संग्रहालय एवं विज्ञान केंद्र प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की आज महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग की प्रमुख परियोजनाओं एवं गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने उनके क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन किया। बैठक में रायपुर में प्रस्तावित साइंस सिटी, रीजनल साइंस सेंटर, विकसित की जा रही अत्याधुनिक एआई गैलरी तथा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित साइंस



पाकों की स्थापना एवं विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आमजन को आधुनिक, इंटरैक्टिव एवं अनुभववात्मक विज्ञान शिक्षा उपलब्ध कराने तथा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में वर्ष 2026–27 के दौरान रायपुर में आयोजित होने वाले 22वें अखिल भारतीय विज्ञान संग्रहालय एवं विज्ञान केंद्र प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों और कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। यह सम्मेलन राष्ट्रीय विज्ञान

संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एनसीएसएम के साथ शीघ्र संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

'समय-सीमा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं':प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आधुनिक विज्ञान अधोसंरचना के विकास को

जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं : मंत्री राजवाड़े

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने शुक्रवार को भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, उपचार व्यवस्था, स्वच्छता तथा अस्पताल संचालन की स्थिति का जायजा लिया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने ओपीडी, वाई, प्रसूति कक्ष, दवा वितरण केंद्र, पेयजल व्यवस्था एवं अस्पताल परिसर की साफ-सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से चर्चा कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में पाई गई कमियों को तत्काल दूर किया जाए तथा



मरीजों को समय पर उपचार, आवश्यक दवाएं एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, दवाओं का पर्याप्त भंडारण बनाए रखने तथा एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता को बेहतर, सुगम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में

किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने तथा गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ

ही अस्पताल परिसर में स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करने पर विशेष जोर दिया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण एवं अंचल क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए इन संस्थाओं में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रभावी एवं व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहना आवश्यक है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को नियमित निगरानी एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए।निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

लाभांडी, तेलीबांधा और देवार डेरा क्षेत्र में पहुंची पुलिस

रायपुर। राजधानी रायपुर में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए शुक्रवार की सुबह 4:30 बजे लाभांडी, बीएसयूपी तेलीबांधा (मरीन ड्राइव) और देवार डेरा क्षेत्र के करीब 350 मकानों में पुलिस ने सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान 8 संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया, जिनमें मारपीट के मामले में पिछले 8 महीने से फरार चल रहा एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल के निर्देशन और सहायक पुलिस आयुक्त (सिविल लाइन) रमाकांत साहू के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में थाना तेलीबांधा और पुलिस लाइन के 80 से अधिक अधिकारी एवं जवान शामिल रहे। जांच के दौरान बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे किरायेदारों और बिना सत्यापन



किरायेदार रखने वाले मकान मालिकों की भी जानकारी जुटाई गई। संदिग्ध पाए गए सभी लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों को समाधान मोबाइल ऐप की जानकारी भी दी और किरायेदारों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराने की अपील की। साथ ही नागरिकों से कहा गया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या डायल-112 पर दें।

आज से बिजली के दाम कम करने तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस करेगी आंदोलन

रायपुर। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिजली के दाम की बढ़ोत्तरी वापस लेने तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने एवं 400 यूनिट तक बिजली बिल हॉफ योजना को फिर से शुरू करने के लिए कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है।

- 1 अगस्त को सभी जिलों में पत्रकार वार्ता लेकर बिजली के दाम बढ़ोत्तरी का विरोध किया जायेगा तथा बिजली के बड़े दाम वापस लिया जाने की मांग की जायेगी।
- 2 अगस्त से कांग्रेस के कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर के खिलाफ घर-घर से आवेदन भरवा कर स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करेंगे तथा आम जनता के द्वारा बिजली के दाम बढ़ाने के विरोध में विरोध पत्र भरवायेंगे, बिजली के दाम बढ़ोत्तरी को वापस लेने की मांग दो महिने तक करेंगे।
- 3 दो माह पश्चात जिलों में भरवाये गये फार्म को लेकर प्रदेश भर में हम जिले के बिजली दफ्तर का घेराव करेंगे एवं एकत्रित

आवेदन जमा करायेंगे, पावती लेंगे।

4. सभी जिलों में फार्म भरवाने तथा जिले के बिजली दफ्तरों के घेराव के बाद प्राप्त पावती को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि बिजली मंत्री भी है उनके निवास का घेराव करेंगे।

● भाजपा सरकार ने जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं के दाम में 30 से 50 पैसे तथा गैर घरेलू में 20 से 40 पैसे की बढ़ोत्तरी किया है। कृषि के पंप की बिजली में भी 40 पैसे की बढ़ोत्तरी की गयी है। भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार पांचवी बार बिजली के दाम बढ़ाये गये है।

● बिजली के बेतहाशा बिल जनता की परेशानी का कारण बने हुये है। हाल ही में भाजपा सरकार ने बिजली के दामों में 12 प्रतिशत विद्युत ईंधन अधिभार (एमपीपीएस) के रूप में बढ़ोत्तरी किया था।

● भाजपा की सरकार आने के बाद अभी तक 31.23 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ाये गये है। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में



केवल 2 पैसे की बढ़ोत्तरी बिजली के दामों में किया था, उसमें भी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू थी।

● भाजपा से सरकार नहीं संभल रही है। वह केवल जनता पर बोझ डालने का काम करती है।

● 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के बाद पांच बार बिजली के दाम बढ़ाया जाना जनता पर बोझ है। सरकार का बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बिल के नाम पर लूटने में लगा है।

● पिछले कुछ महीनों से बिजली के

जैशक्राफ्ट के तहत 30 दिवसीय बांस एवं फर्नीचर निर्माण प्रशिक्षण सम्पन्न

रायपुर। जशपुर जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन की दिशा में संचालित जैशक्राफ्ट पहल के अंतर्गत ग्राम पंचायत झोलांगा के स्व-सहायता समूहों की 50 महिलाओं के लिए आयोजित 30 दिवसीय आवासीय बांस एवं फर्नीचर निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को लोखंडी स्थित महतारी सदन में समापन हुआ। समारोह में सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।समापन समारोह में जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री गंगाराम भगत, ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूहों की महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने कहा कि तुरी एवं बसोंढ़ समाज में बांस शिल्प की समृद्ध परंपरा रही है। सूपा, झोड़ा, टोकरी सहित अनेक पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक डिजाइन और बाजार की मांग के अनुरूप विकसित कर कारीगरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आधुनिक प्रशिक्षण और मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराकर स्थानीय कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है।उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आधुनिक डिजाइन, उन्नत बांस बुनाई तकनीक, मशीनों के माध्यम से कच्चे बांस का प्रसंस्करण तथा आकर्षक फर्नीचर निर्माण का व्यावहारिक



प्रशिक्षण दिया गया।जिससे वे बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर सकें।मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर श्री अभिषेक कुमार ने कहा कि जैशक्राफ्ट के प्रथम चरण का उद्देश्य तुरी समाज की पारंपरिक बांस शिल्प कला को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ना है। इससे स्थानीय कारीगर मूल्यवर्धित एवं प्रतिस्पर्धी उत्पाद तैयार कर बेहतर आजीविका अर्जित कर सकेंगे।समारोह में गुजरात के सूरत से आए विशेषज्ञ प्रशिक्षक श्री राजेश विठ्ठलिया एवं श्री गोपाल विठ्ठलिया को एक माह तक उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्मृति-चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री रोहित व्यास के नेतृत्व तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में लखपति दीदी पहल के तहत महिलाओं की आय में सतत वृद्धि और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैशक्राफ्ट के माध्यम से बांस शिल्प, हस्तशिल्प, छिंद कांसा शिल्प तथा हस्तकरघा जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास, आधुनिक तकनीक, उत्पाद विविधीकरण और विपणन को निरंतर प्रोत्साहित किया जा र

रेल नेटवर्क का विस्तार : परियोजनाओं को आगे बढ़ाने मंत्री ने दिया आश्वासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य की लंबित एवं प्रस्तावित रेल परियोजनाओं को शीघ्र आगे बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और राजनांदगांव के सांसद संतोष पाण्डेय भी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान कटघोरा-डोंगरगढ़, रावघाट-जगदलपुर सहित उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर सहमति बनी और रेल मंत्री ने इन्हें आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रेलवे नेटवर्क का विस्तार छत्तीसगढ़ के संतुलित एवं समावेशी विकास का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक, खनिज, कृषि, पर्यटन और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए आधुनिक रेल संपर्क अत्यंत आवश्यक है। बैठक में करीब 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-डोंगरगढ़ नई रेल लाइन परियोजना पर विशेष सहमति बनी। यह परियोजना



रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से विकसित होगी, जिसके लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जाएगा। यह रेल लाइन कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी तथा अनेक क्षेत्रों को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। करीब 140 किलोमीटर लंबी रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रेलवे की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रेल मंत्री ने इस परियोजना को भी शीघ्र आगे बढ़ाने का भरोसा दिया।

खाद की कालाबाजारी पर 472 जगहों पर हुई कार्रवाई : नेताम

■ 68 हजार बोरी खाद जब्त, 11 लोगों पर एफआईआर

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, खाद की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरे प्रदेश में अब तक 472 जगहों पर कार्रवाई की गई है।

68 हजार बोरी फर्टिलाइजर खाद कृषि विभाग ने जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान 11 दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसके अलावा 11 लोगों पर रस्ट्रुक्र भी दर्ज किया गया है।

मंत्री नेताम ने कहा, बस्तर आज शांति का टापू बना है, बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन मत्स्यपालन इन विभागों के सामूहिक प्रयासों से उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सभी डायरेक्टर और संचालकों ने बस्तर का दौरा किया। जिन क्षेत्रों में काम हो



रहा वहां जाकर देखा, जो हितग्राही, किसान जुड़े हैं, उनसे बात की गई। हमने निर्णय लिया है कि उन क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने का काम होगा, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। एक छत के नीचे सभी विभागों को एक साथ ट्रेनिंग देने की योजना बनाएंगे।

कृषि मंत्री ने कहा, धान और केले की फसल में सर्वाधिक पानी की जरूरत होती है। इन फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। हम अधिकारियों के माध्यम से कृषि संकल्प अभियान चलाकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मियों में धान के बदले दलहन, तिलहन या सब्जी की खेती

● स्मार्ट मीटर से खपत बढ़ा कर फिर खपत ज्यादा होने का हवाला देकर अनुबंध भार बढ़ा दिया जा रहा है और एपीमेंट से अधिक खपत की बात कर बड़े अनुबंध भार के भाजे पर अर्थदंड जोड़कर बिजली के बिल भेजे जा रहे है।

● बिजली बिल ज्यादा आने का तीन कारण है। पहला सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिया है। दूसरा बिजली बिल हाफ योजना बंद हो गई। तीसरा स्मार्ट मीटर लगाए गए है जो अनाप शनाप खपत से अधिक

करते हैं तो पानी की जरूरत कम पड़ेगी। जैविक उत्पादन बढ़ाने, धान के बदले दलहन, तिलहन, फूलों की खेती कर कैसे आगे बढ़ें, इस पर फोकस है।

उन्होंने कहा, कोशिश यह भी है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो, उसकी तुलना में जैविक खाद की दिशा में कैसे आगे बढ़ें, इस पर फोकस है। कम वर्षा में कैसे खेती करें इस पर विभाग फोकस कर रहा है। जल की उपलब्धता हो, इसके लिए कोरबा के बांगो डैम को चिन्हॉकित किया गया है।

मंत्री नेताम ने कहा, पीएम आशा योजना के तहत प्रदेश में पहली बार दलहन तिलहन फसल की खरीदी की गई। एमएसपी के आधार पर खरीदी हो तो किसानों को डर नहीं होता कि वो फसल उगाये या नहीं, लेकिन इस बार खरीदी की व्यवस्था है। आगे चलकर इस योजना पर और भी विस्तार होगा। उन्होंने कहा, किसानों के हित में कोई भी बाधा डालने का प्रयास करेगा उस पर विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा।

रिडिंग बता रहा जिससे बिल अधिक आ रहा है। बिजली के कंपनी के स्मार्ट मीटर लगाये गये है।

● संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अप्रैल 2026 में स्पष्ट किया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर किसी भी उपभोक्ता पर जबरन नहीं थोपे जा रहे हैं, और यह तुरी तरह वैकल्पिक व्यवस्था है और उपभोक्ताओं की सहमति या अनुमति के बिना सामान्य बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलना गैर कानूनी है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर जबरिया क्यों लगाया जा रहा है?

- कांग्रेस मांग करती है कि –
- बिजली के दाम घटाये जाये।
 - 400 यूनिट तक बिजली बिल हॉफ योजना लागू की जाए।
 - स्मार्ट मीटर वापस लिया जाए।
 - उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में स्मार्ट मीटर वहां की भाजपा सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार जनहित में स्मार्ट मीटर वापस ले।

बांकीपुर उपचुनाव में 65.84 फीसदी की खामोशी

सचेंद्र प्रताप सिंह

बांकीपुर उपचुनाव में महज 34.16% मतदान गंभीर राजनीतिक संकेत है। 65.84% मतदाताओं की दूरी जनउदासीनता या असंतोष दर्शाती है। इसे नोटा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट ‘मौन संदेश’ जरूर है। बांकीपुर विधानसभा का हाई प्रोफाइल उपचुनाव अपने परिणाम से पहले ही एक बड़ा राजनीतिक सवाल छोड़ गया है। इस सीट पर सिर्फ 34.16 फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि 65.84 फीसदी मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे ही नहीं। आम तौर पर उपचुनावों में मतदान प्रतिशत कम रहता है, लेकिन जब किसी चर्चित सीट पर राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हों, बड़े नेता प्रचार में उतर रहे हों और चुनावी रणनीति के लिए देशभर में चर्चित व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार हो, तब मतदान का इतना कम प्रतिशत निश्चित रूप से सामान्य राजनीतिक उदासीनता से आगे जाकर विश्लेषण की मांग करता है। बांकीपुर में भाजपा ने प्रचार अभियान में कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे और संगठन ने अपने स्तर पर पूरी ताकत लगाई। दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार के रूप में देशभर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। इस लिहाज से देखें तो चुनाव में राजनीतिक आकर्षण की कमी नहीं थी। बड़े चेहरे थे, प्रचार था, चर्चा थी और मुकाबले को लेकर देशभर में उत्पुकता थी। इसके बावजूद यदि दो-तिहाई से अधिक मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मतदाता की प्राथमिकता क्या थी और उसने चुनाव से दूरी क्यों बनाई? इस पूरे मामले में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। यदि मतदाता किसी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं था या उसे चुनाव मैदान में मौजूद किसी भी प्रत्याशी पर भरोसा नहीं था, तो उसके पास ईवीएम में नोटा का विकल्प मौजूद था। वह मतदान केंद्र तक जाकर अपनी असहमति दर्ज करा सकता था। लेकिन यहां सवाल यह है कि बड़ी संख्या में लोगों ने नोटा का विकल्प चुनने के बजाय मतदान केंद्र तक जाना ही क्यों उचित नहीं समझा? इसलिए 65.84 फीसदी लोगों का मतदान से बाहर रहना केवल उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी मान लेना शायद इस पूरे घटनाक्रम को बहुत सीमित नजरिए से देखने जैसा होगा। नोटा दबाने वाला मतदाता चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अपनी असहमति व्यक्त करता है, जबकि अपक्षीय मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचने वाला मतदाता चुनावी प्रक्रिया से ही दूरी बना लेता है। दोनों स्थितियों के राजनीतिक अर्थ अलग-अलग हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि बांकीपुर में मतदान से दूर रहने वाले लोग वास्तव में उदासिन थे या उनके भीतर किसी प्रकार का राजनीतिक असंतोष था। क्या उन्हें लगाना कि कोई भी उम्मीदवार उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा, या फिर उन्हें यह विश्वास ही नहीं रहा कि उनका एक वोट उनकी जिंदगी में कोई ठोस बदलाव ला सकता है? देश में पिछले कुछ समय से छाओं और युवाओं के विरोध प्रदर्शन, किसान आंदोलन, राम मंदिर के चंदे को लेकर उठे सवाल, भरत तिवारी एनकाउंटर का विवाद, कमर तोड़ती महंगाई, पथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का मुद्दा, बेरोजगारी और आम नागरिक से जुड़े अनेक दूसरे सवाल लगातार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि इन सभी मुद्दों ने सीधे तौर पर बांकीपुर में मतदान प्रतिशत कम किया, क्योंकि उसके लिए ठोस आंकड़ों और मतदाताओं के प्रत्यक्ष अध्ययन की जरूरत होगी। लेकिन यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि क्या इन मुद्दों ने मतदाताओं के एक हिस्से में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निराशा, असंतोष या उदासीनता पैदा की है?

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

सालों द्वीप और सातों समुद्र कहाँ है ?

पुराणों में- लम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर नाम सात द्वीपों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल नामक सात समुद्रों का वर्णन आता है। पुराणों में इन सबका जिस प्रकार का वर्णन किया है वे इदमित्थं वैसे ही भूमण्डल की विस्तृत सीमा के अन्धन्तर-सूक्ष्म जगत् के संस्थान में उपलब्ध हो सकते हैं, जैसा कि हम पीछे पौराणिक भूगोल शैली की विशेषता प्रघट्ट में प्रकाश कर आये हैं। कदाचित् शङ्खुवादी महाशयों को अब भी दूध दही आादि के समुद्रों पर विश्वास न हो तो हम इस विषय में साक्षात् निराकार भगवान् की गवाही भी दिलवा सकते हैं, जिससे कम से कंभ अस्तित्व समाज को तो इनके अस्तित्व पर कुछ भी सन्देह शेष न रहे। यथा –

घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः, क्षीरेण पूर्णा उदकेन

दन्धा।

एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः, स्वर्ग लोके मधुमत्पिन्यमानाः।

(अर्धव 4।34।16) अर्थात् घी, मधु, दही और जल से परिपूर्ण हृद-तड़ग- झील समुद्र धारा रूप में तुझे तृषयं प्राप्त हों। उपर्युक्त मन्त्र में बड़ी ही खुबि के साथ परोक्षभूत एवं आश्चर्यकारक घृतोद, इक्षुरसोद, सुरोद, क्षीरोद, दधिमण्डोद और मिष्टजलोद इन छहों समुद्रों का वर्णन विद्यमान है। सातवां लवणोद नामक सरा समुद्र प्रत्यक्ष ही है। अतः वेद के इस मन्त्र में उसे परिगणित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

यहाँ तक हमने पौराणिक भूगोल-वर्णित अमुक अमुक वस्तुओं के न मिलने की शिकायत का निराकरण किया है, तदनुसार विज्ञ पाठक यह समझ चुके होंगे कि क्योंकि पौराणिक भूमण्डल का क्षेत्र दिव्य जगत् तक विस्तृत है।

क्रमशः ...

समाज को कहाँ ले जाएगी असभ्यता को सही साबित करने की कोशिश

ओश चतुर्वेदी

गाली इन दिनों राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में हैं। जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी खुलेआम गंदी गालियां इसका बहाना बनीं हैं। हैरत की बात है कि इसमें कई प्रोफेसर और पत्रकार भी शामिल हो गए हैं और इन गालियों को उचित ठहराने की दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। इसे लड़कियों की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति बताया जा रहा है तो कई गालीबाजों को नई गालियां रचने का सुझाव दे रहा है। उनके हिसाब से सारी गालियां पुरुषों द्वारा रची गई हैं, लिहाजा लड़कियों को नई तरह की गाली पुराण रचना चाहिए। इसके खिलाफ का समाज का एक बड़ा तबका इस नई प्रवृत्ति की मुखालफत कर रहा है। उसका कहना है कि गालियां भले हों समाज में सदा से चली आ रही हैं, लेकिन कम से कम उनकी सार्वजनिक स्वीकृति नहीं रही है। इतिहास गालियों के समर्थकों में सबसे बड़ी संख्या खुद को क्रांतिकारी मानने वाले वामपंथी हैं। प्रागतिशील लेखक संघ भारत में वामपंथी विचारधारा के लिहाज से गठित हुआ था। उसके पहले अध्यक्ष उपन्यास सम्राट प्रेमचंद थे। गाली विमर्श के संदर्भ में प्रेमचंद का लिखे एक लेख का अंश याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है, ‘हर जाति का बोलचाल का ढंग उसकी नैतिक स्थिति का पता देता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हिन्दुस्तान सारी दुनिया की तमाम जातियों में सबसे नीचे नजर आएगा। बोलचाल की गंभीरता और सुधरापन जाति की महानता और उसकी नैतिक पवित्रता को व्यक्त करती है और बदजबानी नैतिक अंधकार और जाति के पतन का प्रका प्रमाण है। जितने गन्दे शब्द हमारी जबान से निकलते हैं शायद ही किसी सभ्य जाति की ज़बान से निकलते हों।’

इसमें दो राय नहीं कि हर सफल आंदोलन के बाद आंदोलनकारी नायक और विजेता के रूप में उभरते हैं। इस लिहाज से काकरोच जनता पार्टी के नेता जंतर-मंतर आंदोलन के फिलहाल के विजेता तो हैं हीं। इस तर्क से उनका साथ देने वाला वाला समूह भी उसी वर्ग का माना जाएगा। इतिहास हमेशा



विजेताओं का ही गुणगान करता है, उसकी सफलता की बलैया लेता है। चूँकि काकरोच जनता पार्टी के नेता चूँकि हीरो हैं, इसलिए उनकी ओर से दी गई गालियों को उनके गुणों के रूप में देखने की कोशिश हो रही है। तर्क दिया जा रहा है कि भारतीय समाज में शादी-ब्याह और मुंडन-जेनेऊ के मौके पर प्यार से गालियां दी जाती हैं। लिहाजा से जंतर-मंतर की गालियां भी उन्हीं गालियों की तरह सहे की अभिव्यक्ति हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है ? गंभीरता से विचार करेंगे तो इसका जवाब ना में मिलता है। इस अश्लील अभिव्यक्ति का मकसद देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए हिकारत और घृणा का प्रदर्शन है। मोदी देश के वामपंथी और कांग्रेसी इकोसिस्टम एवं संस्कृति और परंपराभंजकों के निशाने पर तब से हैं, जब आज के जेन जी के अधिसंख्य जन्मे भी नहीं होंगे। अतीत में मोदी के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल जरूर होता था, लेकिन उनमें गालियां नहीं थीं। जंतर-मंतर का हालिया आंदोलन इसी बुनियाद पर आगे की कड़ी है।

बचाव में उतरे वामपंथियों का तर्क है कि ये गालियां नई नहीं हैं। कई तो खुद का उदाहरण देते हुए कहने से नहीं चूक रहे कि वे भी गाली देते हैं या फिर उनके दोस्तों के बीच गालियों का खूब आदान-प्रदान होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे ऐसी ही गालियां अपने ही बच्चों के मुख से अपने ही घरों में सुनना पसंद करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या इन गालीबाजों को भविष्य में वे अपने परिवार का दामाद या बहू के रूप हिस्सा बनाना पसंद करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या वे अपने ही बच्चों से स्रेह के तौर पर

ज्ञान/मीमांसा

क्या उपद्रवियों की एफआईआर वापस ले सकती है सरकार?

अभिनय आकाश

सड़कों पर ऐसा हंगामा मचा कि लगा देश

की राजधानी दिल्ली नहीं, बल्कि किसी बॉलीवुड की फुल-ऑन एक्शन फिल्म का सेट बन गई हो! मामला नीट पेपर लीक का था और मैदान में उतरी थी अपनी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)। मांगने तो आए थे शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा और अपनी तमाम शर्तें पूरी कराने की जिद्द, लेकिन सोमवार 20 जुलाई को कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि सीधे सुरक्षा की धन्जियां उड़ गईं। प्रशासन ने सीधे-सादे तरीके से जंतर-मंतर पर धरना देने की परमिशन क्या दी, सीजेपी के सुरमों को लगा कि पूरी दिल्ली ही उनकी है! जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था, इन लोगों ने बैरिकेड तोड़ो, आगे बढ़ो का नारा पकड़ लिया और हाई-सिक्योरिटी वाले नो-एंट्री इलाके में संसद घेराव करने के लिए कूच कर दिया। फिर क्या था? शांतिपूर्ण प्रदर्शन का चोला उतरा और सड़कों पर पत्थरबाजी, खौंचतान और सुरक्षाकर्मियों के साथ जबरदस्त एक्शन मोड ऑन हो गया। दिन-दहाड़े राजधानी की सड़कों पर ऐसा गदर काटा गया कि सरकार से लेकर आम जनता तक, सब धम-से गए। सीजेपी के नेता अपनी जिद पर अड़े रहे, उपद्रवी सड़कें जाम करके सरकार की नाक में दम करते रहे और आखिर में केंद्र सरकार को घुटने टेककर उनकी सारी शर्तें मानने का वादा करना पड़ा। जंतर-मंतर के शांत कोने से शुरू होकर संसद के दरवाजे तक पहुँचने वाले इस हाई-वोल्टेज पॉलिटिकल थ्रिलर ने पूरे देश को सन्न करके रख दिया!

सीजेपी नेताओं की एक मांग यह थी कि सरकार किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। उन लोगों के खिलाफ भी नहीं जिन्होंने विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया, हंगामा किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर वापस ले ले। साफ है कि पार्टी उन उपद्रवियों को बचाने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने हिंसा के जरिए सरकार पर दबाव बनाया है उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से सुरक्षाकर्मियों को बल प्रयोग करना पड़ा। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन में और उसके आसपास मौजूद लोगों की दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच में पाया



गया कि भीड़ में शामिल बड़ी संख्या में लोगों का पहले से अपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हैरानी की बात है और देश के आम, कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए निराशाजनक भी, कि केंद्र सरकार ने इस मांग को भी मान लिया। सरकार के इस फैसले से देश के आम नागरिकों के मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे: क्या देश की चुनी हुई सरकार को उपद्रवियों के सामने इस कदर ब्लैकमेल किया जा सकता है? क्या सड़कों को बंधक बनाने वाले, सरकारी संपत्ति को फूँकने वाले और समाज के ताने-बाने को तात-तार करने वाले हुड़दगियों को यूँ ही साफ़-साफ़ बाइजन्त बरी होने दिया जाएगा? और अगर किताबी-कानूनी भाषा में बात करें, तो क्या देश को कार्यपालिका के पास इतनी ताकत है कि वो एक बार शुरू हो चुकी कानूनी प्रक्रिया का गला घोट दे? क्या सरकार के पास वाकई यह कानूनी अधिकार या वीटो पावर है कि वो उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले ले, जिन्होंने पूरे देश की राजधानी को ब्लैकमेल करके रख दिया था? आइए, इन सवालों के कानूनी जवाब तलाशने के लिए कानून की किताबों के फने पलटते हैं!

आपराधिक कानून किसी अपराध को सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ़ नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ़ गलत काम मानता है। यही वजह है कि जब भी कोई अपराध होता है, तो राज्य अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाता है। यह नियम एक कानूनी सुरक्षा के तौर पर काम करता है, जिसका मकसद कमजोर पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। इस कानूनी सुरक्षा का ही एक हिस्सा यह नियम भी है कि एक बार जब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसे अदालत की मंजूरी के बिना रोकना नहीं जा सकता। कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का एक तरीका है अपराध के बारे में एफआरआर दर्ज कराना। एक बार जब किसी अपराध के लिए

एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो इसे अदालत की मंजूरी के बिना रद्द या वापस नहीं लिया जा सकता। इस नियम के पीछे मकसद यह है कि पीड़ित पर किसी प्रभावशाली या ताकतवर अपराधी के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई न करने का दबाव न डाला जा सके। मौजूदा हालात में भले ही सरकार ने हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने का वादा किया हो, लेकिन वह सीधे ऐसा नहीं कर सकती। हालाँकि, कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जिनके तहत एफआईआर वापस ली जा सकती है या कानूनी कार्यवाही रोकी जा सकती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में एक कानूनी प्रावधान है जो आपराधिक मुकदमे में शामिल पक्षों को कोर्ट के बाहर या पूरे मुकदमे की प्रक्रिया से गुज़रे बिना मामले को सुलझाने की इजाजत देता है। हालाँकि, यह सुविधा केवल कुछ छोटे अपराधों के लिए ही मिलती है, जिनका अस्र आमतौर पर निजी हितों पर पड़ता है और जिन्हें बीएनएसएस के तहत कंपाउंडेल (समझौता-योग्य) अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। कंपाउंडेबल अपराधों की सूची बीएनएसएस की धारा 359 में दी गई है और वे इसी धारा के तहत आते हैं। कंपाउंडेबल अपराधों के कुछ उदाहरण हैं – मामूली चोट पहुँचाना, धोखाधड़ी, घर में बिना इजाज़त घुसना, गलत तरीके से रोकना के कुछ मामले और चोरी। रेप, हत्या, दंगा और डकैती जैसे गंभीर अपराध कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। जहाँ कुछ कंपाउंडेबल अपराधों में कोर्ट की इजाज़त के बिना समझौता किया जा सकता है, वहीं कुछ मामलों में कोर्ट की मंजूरी ज़रूरी होती है। सरकार इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी क्योंकि सीजेपी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की घटनाएँ – जैसे सुरक्षाकर्मियों पर हमला, पत्थरबाजी, और पुलिस की गाड़ियों व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना – निश्चित रूप से कंपाउंडेबल अपराधों की श्रेणी में नहीं आती हैं। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

अच्छी बात यह है कि एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद, उसे या मामले को वापस लेना एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, मामला न्यायपालिका के हाथ में आ जाता है। एग्जीक्यूटिव संबंधित पुलिस स्टेशन को एफआईआर वापस लेने का आदेश नहीं दे सकता और न ही संबंधित कोर्ट या मजिस्ट्रेट को

एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई न करने का निर्देश दे सकता है। यह व्यवस्था पीड़ित और यहां तक कि कमजोर राज्य को भी ताकत के दम पर किए जाने वाले दबाव या जबरदस्ती के आगे झुकने से बचाती है। इससे यह सवाल उठता है कि अगर कानून एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) को एफआईआर रद्द करने या वापस लेने की ताकत नहीं देता है, तो सरकार ने हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने का वादा क्यों किया? खेर, एक और तरीका है जिससे आरोपी को बरी किया जा सकता है या केस बंद किया जा सकता है, और वह है पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस बीएनएसएस की धारा 193 के तहत क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट दाखिल करती है। यह रिपोर्ट उन मामलों में दाखिल की जाती है जिनमें पुलिस को एफआईआर में बताए गए अपराध के होने का कोई शुरुआती सबूत नहीं मिलता, आरोपी का पता नहीं चल पाता, या शिकायत झूठी पाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं। क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने से ही केस बंद नहीं हो जाता; यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोर्ट क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार करता है या आगे जांच का आदेश देता है। अगर कोर्ट पुलिस की जांच से संतुष्ट है, तो वह क्लोज़र रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है और केस बंद कर सकता है। ऐसे में एफआईआर रिकॉर्ड पर बनी रहती है, लेकिन केस बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोर्ट पुलिस की जांच के नतीजों से संतुष्ट नहीं है, तो वह आगे जांच का आदेश दे सकता है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि सीजेपी विरोध प्रदर्शनों के दौरान जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, उन्हें कानून का सामना करना ही होगा। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर अधिकारियों को पहले से दर्ज सड़क की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों, दोनों के खिलाफ लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हालाँकि, शीप अदालत ने उन राज्यों को निर्देश दिया जहां ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए थे कि वे बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दें। सर्वोच्च न्यायालय का यह रुख सीजेपी नेतृत्व को पसंद नहीं आया, जो ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे और उनके गुंडे कानून से ऊपर हों।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्मृति दिवस

अनन्या मिश्रा

भारत के प्रमुख नेता, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और लोकप्रिय नेता बाल गंगाधर तिलक का 01 अगस्त को निधन हो गया था। उनके नाम के आगे लोकमान्य लगाया जाता है, जोकि उन्होंने अर्जित की थी। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उनका पूरा जीवन ही आदर्श था।

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 13 जुलाई 1856 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। वह संस्कृत के विद्वान और प्रख्यात शिक्षक थे। उनकी मां का नाम पार्वती बाई गंगाधर था।

बाल गंगाधर तिलक प्रखर राष्ट्रवादी,

हिन्दूवादी नेता एवं बहुमुखी

प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे।

वे समाज सुधारक, राष्ट्रीय नेता, थे जिन्हें भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिन्दू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान में महारथ हासिल थी।

तिलक ने ही सबसे पहले

ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग

उठाई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार

है और मैं इसे ले कर रहूँगा। इस नारे ने

बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया था।

आजादी के परवानों के लिए ये महज कुछ

शब्द भर नहीं थे बल्कि एक जोश, एक

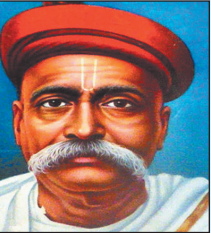
जुनून था जिसके जरिए लाखों लोगों ने

अपनी कुर्बानियां देकर मां भारती को

अंग्रेजों से आजादी दिलाई। इस वाक्य को

पढ़ने और सुनने वाले की बाल गंगाधर

तिलक की याद आ ही जाती है। लोकमान्य



का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत

किया गया नेता। लोकमान्य के

अलावा इनको हिंदू राष्ट्रवाद

का पितामह भी कहा जाता है।

अखण्ड भारत का स्वप्न

देखने एवं उसे आकार देने

वालों में प्रखर राष्ट्रवादी नेता

तिलक पश्चिमी शिक्षा पद्धति

के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था

इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को नीचा

दिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति को

गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अंग्रेजी शिक्षा के ये आलोचक थे। इस

वजह से ये मानते थे कि यह भारतीय

सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। कुछ

सोच विचार के बाद वे इसी नतीजे में पहुंचें

कि एक अच्छा नागरिक भी बन सकता

है, जब उसे अच्छी शिक्षा मिले। भारत में

शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अपने

मित्र के साथ मिलकर ‘डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी’ की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में भी काफी काम किया। तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेजों ने तिलक को 1906 में विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर 6 साल की सजा सुनाई और बर्मा के एक जेल में डाल दिया तो जेल में महान किताब गीता रहस्य लिख डाली जो तिलक जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है।

बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से एक करीबी संधि बनाई, जिनमें बिपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविन्द घोष, वी0 ओ0 चिन्मयम पित्रे और मुहम्मद अली जिन्नाह शामिल थे।

आज का इतिहास

- 1883 इनलैंड डाक सेवाओं का आरम्भ ग्रेट ब्रिटेन में किया गया।
- 1902 ऑस्ट्रेलिया के वोलांगोंग शहर में पिट विस्फोट में 100 लोग मारे गए।
- 1907 रॉबर्ट बैडेन-पॉवेल ने स्काउटिंग आंदोलन की शुरुआत करते हुए इंग्लैंड के डोसेट में ब्राउनस्कैलैंड में पहला स्काउट शिविर आयोजित किया।
- 1907 रॉबर्ट बैडेन-पॉवेल इंग्लैंड के ब्राउनसेआ आइलैंड पर पहला स्काउट शिविर ले गए।
- 1914 इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी एवं रूस द्वारा की गयी।
- 1914 यूरोप में युद्ध के कारण न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद किया गया।
- 1924 सऊदी अरब के राजा शाह अब्दुल्ला का जन्म हुआ।
- 1944 द्वितीय विश्व युद्ध-पोलिश होम आर्मी ने पोलैंड के नाजी कब्जे के खिलाफ वारसां विद्रोह इनवर्स शुरू किया, एक विद्रोह जो 63 दिनों तक चला था जब तक कि यह जर्मनों द्वारा खारिज नहीं किया गया था।
- 1946 संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गयी।
- 1960 पाकिस्तान की पुरानी राजधानी को कराची से बदलकर इस्लामाबाद में तबदील कर दिया गया।
- 1965 ब्रिटिश टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापन प्रतिबंधित किया गया।
- 1971 अंतरिक्ष यात्री जेम्स इरविन और डेविड स्कॉटकेम चंद्र रोवर पर चंद्रमा सफारी के दौरान जेनेसिस रॉक नामक चट्टान के पार। यह लगभग 4,500 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है।
- 1976 सिएल सीहॉक्स ने अपना पहला फुटबॉल गेम खेला।
- 1981 अमेरिकन केबल टेलीविजन नेटवर्क, संगीत के लिए पहला समर्पित-आधारित आउटलेट, द बगल्स द्वारा संगीत वीडियो फेस्टी गीत वीडियो क्लिड द रेडियो स्टार के साथ अपनी शुरुआत की।
- 1984 वाणिज्यिक पीट-कटर ने उत्तरी पश्चिम इंग्लैंड के चेशायर के लिंडो मॉस में अमन के संरक्षित दलदल की खोज की, जिसे लिंडो मैन कहा जाता है।
- 1995 शनि के एक और चन्द्रमा की खोज हबबल दूरबीन द्वारा की गयी।
- 1997 स्टीव जॉन्स ने बोस्टन शहर के मैकवर्ल्ड, एमिल कॅप्यूटर और ईकन से दोहरा जुड़े।
- 2000 इरान में पहली बार महिलाओ को भी मद्रस्सों में इमाम बनाने का अधिकार दिया।

पंजाब कांग्रेस बुरी तरह बिखराव की शिकार

प्रो. दरबारी लाल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलाकमान ने पंजाब के चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले कांग्रेस को सुनियोजित, सुनिश्चित और सुसंगठित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया, जिसमें अपने महारथियों और राजनीति में गहन तजुर्बा रखने वाले धुरंधर नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपीं, ताकि वे उन्हें खूबसूरत तरीके से सरअंजाम देकर कांग्रेस को पंजाब में सत्तासीन कर सके और लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करके पंजाब में शांति, समृद्धि और विकास की नीतियों को अमलीजामा पहना सकें। परंतु चंद रोज बाद पंजाब कांग्रेस के एक बड़े गुट ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि वह न तो प्रदेश प्रधान के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और न ही उसका समर्थन करेंगे। इस खबर ने पंजाब के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को मायूस ही नहीं किया, बल्कि उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस बुरी तरह बिखराव की शिकार है।

हकीकत में पंजाब कांग्रेस के लंबे इतिहास में पहली बार कांग्रेस के एक बड़े गुट ने

आलाकमान को पार्टी हित में सुझाव दिया है, चुनौती दी है या बगावत की है। जब पिछले साढ़े 4 वर्षों से प्रदेश प्रधान को सहयोग दे रहे थे तो फिर चुनावों के नजदीक उसको बदलने के लिए आलाकमान पर दबाव क्यों डाला जाने लगा? यह मंसूबा समझ से परे है, संशयपूर्ण है और दाल में कुछ काला तो जरूर लगता है।

इतिहास साक्षी है कि सभी राजनीतिक दलों के आलाकमान ही सर्वोपरि होते हैं और प्रदेशों में नियुक्तियां भी उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। कई बार वे प्रदेशों के प्रतिष्ठित नेताओं से सलाह-मशविरा कर लेते हैं और कई बार अपनी रिपोर्ट के आधार पर नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। जिन्हें बिना किसी किंतु-परंतु के प्रदेश का पार्टी नेतृत्व सहर्ष स्वीकार कर लेता है। यही परम्परा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और भविष्य में भी ऐसे ही चलती रहेगी। कांग्रेस भारत की 141 वर्ष पुरानी आलीशान और गौरवमयी इतिहास की पार्टी रही है और उसका शीर्ष नेतृत्व ही प्रदेशों से संबंधित फैसला लेते आया है। ये फैसले राजनीतिक तौर पर फलदायक रहें या नुकसानदायक, यह चर्चा का विषय हो सकता



है। एक गुट के दबाव में यदि आलाकमान घुटनों पर आ जाती है तो फिर दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे बगावती सुर उठने लगेंगे, जो उनके अधिकार क्षेत्र को ही चुनौती होगी। यदि कोई मांग उचित भी हो तो उसका समाधान करने का तरीका युक्तिसंगत, समयानुकूल और हालाते हाजरा की जरूरीयात के मुताबिक हो। समस्या को लटकाना भी समस्या का समाधान नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के प्रादेशिक संगठनों में यदि गुटबाजी है तो आलाकमान भी अपनी कमियों, कमजोरियों और गुटों को प्रोत्साहित करने की गैर-मामूली जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। पंडित नेहरू और सरदार पटेल के

समय भी 2 गुट थे, परंतु दोनों के मुख्य उद्देश्य बड़े सकारात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक थे।

वह पार्टी के हितों से ऊपर राष्ट्र के हितों को ही सर्वोच्च मानते थे। एक ने समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया और दूसरे ने इन प्रदेशों में पांव नहीं जमे। हकीकत में बुनियाद रखी। वर्तमान समय में गुटबाजी निजी

स्वार्थों तक सीमित होती जा रही है जो अति विनाशकारी साबित हो रही है। कांग्रेस आलाकमान पहले ही जल्दबाजी, गुटबाजी और खुशामदियों के सलाह-मशविरे से असम गंवा बैठी है। हरियाणा में जीतती-जीतती पराजित हो गई और पंजाब में जिस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहते थे, वही कांग्रेस को ले डूबा और पार्टी विधानसभा में 18 सीटों तक सीमित रह गई। यह जानते हुए भी कि युद्ध के मैदान में घोड़े नहीं बदले जाते, फिर भी उन्होंने चुनाव से कुछ महीने पहले केप्टन अमरिंदर सिंह को बदल कर हिमालय से भी बड़ी गलती

की। हकीकत में लोकप्रिय नेता को बदलने का न समय ठीक था और न ही फैसला, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा राजनीति शतरंज के मोहरों की तरह शह और मात का खेल होता है। मामूली गलती से कई बार बादशाह भी मारा जाता है।

कांग्रेस के ठीक समय पर ठीक फैसले न लेने से तमिलनाडु, बंगाल, यूपी. और बिहार हाथ से निकल गए और आज तक कांग्रेस के इन प्रदेशों में पांव नहीं जमे। हकीकत में कांग्रेस का संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रकोष्ठ अति कमजोर हो चुके हैं। प्रदेशों के संगठनात्मक ढांचे भी शिथिल हो रहे हैं। देश में 90 करोड़ मतदाताओं में आधी महिलाएँ हैं, परंतु महिला कांग्रेस का प्रभाव भी फीका पड़ रहा है। युवा कांग्रेस, कांग्रेस का एक मकबूल और शक्तिशाली फोर फ्रंट था, जो अब कई छोटे-छोटे संकीर्ण गुटों में बंटा हुआ है। इन पर भी प्रभावशाली विधायकों और मंत्रियों का नियंत्रण है। इंटक कांग्रेस का एक बड़ा ही शक्तिशाली विंग था, जिसमें लाखों औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि क्षेत्र से संबंधित मजदूर होते थे जो अब अपना वर्चस्व खो चुका है। इसी तरह सेवा दल, जिसके

मुखिया कभी पंडित नेहरू थे, आज थोड़े से लोगों के हाथों में सिमट कर रह गया है। जबकि आर.एस.एस. की भारत में करीब 80 हजार के लगभग शाखाएं हैं, जो हर समय सक्रिय रहते हैं। यद्यपि कांग्रेस के पास आज भी करोड़ों कार्यकर्ता हैं, पर उन्हें एकता के सूत्र में बांधने वालों की भारी कमी है।

‘आप’ सरकार मुफ्तखोरी के नाम पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है। अकाली दल पिछले चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बाद अभी भी हिचकोले खा रहा है। भाजपा इतिहास में पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़कर कुछ नया करने के लिए संकल्पित है। चुनाव के नजदीक आने पर भी कांग्रेस के पांव देवताओं की तरह जमीं को छूते नजर नहीं आ रहे।

खुदा पंजाब कांग्रेस पर नज़रे इनायत रखे। इस संबंध में एक शेर नजर करता हूं। आदमी खुद को कभी यूं भी सजा देता है, अपने दामन से खुद शोलों को हवा देता है। मुझे उस सियासतदान की सियासत पर तरस आता है, जो अपने मफाद के लिए पार्टी हितों को कुर्बान करता है॥

इस्तीफा तो हो गया लेकिन क्या छात्रों को न्याय मिला?

कतिलाल मांडेत

कई दिनों के धरना-प्रदर्शन के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहली नजर में इसे आंदोलन की बड़ी जीत और लोकतंत्र की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न वही है, जो हर छात्र और अभिभावक के मन में है—क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो गया? क्या इससे पेपर लीक की समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता लौट आएगी? क्या लाखों विद्यार्थियों की मेहनत अब बिना किसी भय के रंग जाएगी? इन सभी सवालों का उत्तर फिलहाल नकारात्मक दिखाई देता है। यही कारण है कि आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन केवल एक मंत्री के इस्तीफे से नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में आने वाले वास्तविक सुधारों से किया जाना चाहिए। सबसे पहले उस बात का उल्लेख आवश्यक है जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अभिजीत दीपक ने मंच से कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने इसे अपनी और लोकतंत्र की जीत बताया। निस्संदेह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है और यदि सरकार ने छात्रों के दबाव के बाद निर्णय लिया है तो यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत माना जा सकता है। लेकिन यहां यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि दीपक की राजनीतिक या आंदोलनकारी जीत अपनी जगह हो सकती है, परंतु उस छात्र को इससे क्या मिला जिसकी एक वर्ष की मेहनत पेपर लीक के कारण बर्बाद हो गई? जो विद्यार्थी मानसिक तनाव में आ गया, जिसने दोबारा परीक्षा दी, जिसने आर्थिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना किया, उसके जीवन में अभी तक कोई ठोस परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसलिए केवल सुविधियों में आने या आंदोलन की सफलता

का दावा करने से छात्रों की वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं हो जातीं। धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के बाद जारी पत्र में कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की थी और उनका उद्देश्य किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देना था। उन्होंने यह भी कहा कि देश की युवा शक्ति उनके लिए सर्वोपरि है और राष्ट्रहित तथा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पद छोड़ा। यह एक जिम्मेदार राजनीतिक संदेश है। इसी तरह सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, मुकदमे वापस लेने की बात कही, पीड़ित छात्रों के लिए मुआवजे की घोषणा की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर चर्चा का भरोसा दिया। हिंसा और तनाव के बावजूद सरकार ने अंततः संवाद का रास्ता चुना। यह किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक माना जा सकता है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि किसी मंत्री का इस्तीफा स्वयं में समाधान नहीं होता। पेपर लीक जैसी घटनाएं किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पूरे तंत्र की कमजोरी का परिणाम होती हैं। यदि व्यवस्था में खामियां बनी रहेंगी तो नया मंत्री भी उन्हीं चुनौतियों का सामना करेगा। छात्रों को मंत्री बदलने से नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने से लाभ मिलेगा। आज देश के करोड़ों विद्यार्थी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या अब पेपर लीक पूरी तरह बंद हो जाएगा? दुर्भाग्य से इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताओं और संगठित नकल गिरोहों के सक्रिय होने की घटनाएं सामने आई हैं। इसका अर्थ है कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का रूप ले चुका है। ऐसे नेटवर्क में छोटे-छोटे एजेंटों से लेकर आर्थिक लाभ उठाने वाले बड़े मास्टरमाइंड तक शामिल होते हैं। कारवां अब अक्सर निचले स्तर तक सीमित रह जाति है जबकि पूरे षड्यंत्र को संचालित करने वाले लोग बच निकलते हैं।

राजनीतिक विद्वेष की भेंट ना चढ़े महिला आरक्षण विधेयक के उद्देश्य

विक्रम उपाध्याय

यह सभी मानेंगे कि महिला आरक्षण बिल का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की न सिर्फ राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना, बल्कि उनमें संभावित राजनीतिक नेतृत्व के गुणों को भी उभार कर समाज में उसको मान्यता देना भी है। महिला आधिकारिता और महिला आरक्षण, ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अफसोस कि विरोधी दल आधी आबादी को दबाए रखने की रणनीति पर कायम हैं।

वे दिखावे के लिए महिला आरक्षण बिल के समर्थन का स्वांग करते हैं, लेकिन जब किसी महिला को नेतृत्व देने की बात आती है तो येन केन प्रकारेण उसको टालने का कुचक्र रच देते हैं। इस मामले में एक उदाहरण महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री का ही लिया जा सकता है। कांग्रेस और एनसीपी (पवार) के नेता लगातार सुनेत्रा पवार के खिलाफ प्रचार और विरोध में लिस दिखाई दे रहे हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट है। सरकार इसके जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीधे चुने जाने वाले सभी प्रतिनिधियों की संख्या कम से कम 33 प्रतिशत करना चाहती है। यानि कुल सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहती है।

यदि ऐसा हो जाता तो इससे न केवल भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती, बल्कि समाज के नजरिए में भी एक बड़ा बदलाव आता। 21 वीं सदी की महिलायें देश के विकास से जुड़े सभी निर्णयों में शामिल होती और वे स्वयं इसमें बड़ा योगदान करतीं।

लेकिन विपक्ष के अडियल रवैये और नारी जाति के विकास में बाधा डालने की

उनकी सोंच ने इस विधेयक को पास होने नहीं दिया। जो लोग लोकसभा में अपने संख्या बल के जरिए अपने एजेंडे की पूर्ति को ही लोकतंत्र समझ रहे हैं, वे एक बड़ी भूल कर रहे हैं। बिल पारित करने के लिए संसद में आवश्यक समर्थन देने से मना करने वाले यह जान केलें कि देश उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुली आँखों से देख रहा है। जनता समझ रही है कि वे आधी आबादी के प्रति क्या नजरिया रखते हैं।

उनके कारण यदि महिलाओं को उनकी नेतृत्व क्षमता पर अनुचित सवालों का सामना करना पड़ता है, तो साफ है कि विपक्ष के लोग महिला सशक्तिकरण की भावना नहीं रखते। यह सही है कि सिर्फ कानून बनाने से राजनीतिक संस्कृति नहीं बदल जाती। जब तक राजनीतिक दलों में इस बात की चेतना नहीं जगती कि महिलाएं दशकों से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रही हैं,

उनको समाज में आगे लाने के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है, तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। किसी भी राजनीतिक दल को महिला का सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कहने को तो महिला आरक्षण अधिनियम का समर्थन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा भी कर रही हैं एनसीपी (पवार) की नेता सुप्रिया सुले भी इस अधिनियम को जल्द लागू करने की मांग कर रही हैं,

लेकिन जब बात इस पर अमल की आती है तो इसे टालने के बहाने भी इन्हीं की तरफ से आ जाते हैं। इसका उदाहरण सामने है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। प्रतीकात्मक ही सही लेकिन महाराष्ट्र के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की



धरती से सुधार आंदोलनों की एक शृंखला रही है।

राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति का महत्व भी इसी सुधार के साथ देखा जाना चाहिए था, क्योंकि छह दशकों से अधिक समय से चली आ रही एक संस्थागत बाधा को तोड़ कर राज्य में एक महिला को सत्ता के शीर्ष पर बिठाया गया था। सुनेत्रा पवार ने भी दिखाया कि आगे बढ़कर वह नेतृत्व कर सकती हैं।

सुनेत्रा पवार ने इस साल जनवरी में अपने प्रति अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद यह पद संभाला है। इससे पहले वे राज्यसभा में थीं। उनकों समर्थन और समय देने के बजाय विपक्ष सार्वजनिक रूप से इस बात की चर्चा में लगा गया है कि वह नेतृत्व करने में सक्षम हैं कि नहीं, जबकि उन्हें खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला है।

सरकार के काम काज की जाँच-परख होनी ही चाहिए। मंत्रियों से भी सवाल-जवाब होने चाहिए। लेकिन कामकाज के मूल्यांकन के बहाने किसी महिला नेता को ही राजनीतिक लड़ाई का मुख्य निशाना नहीं बनाना चाहिए। इससे तो महिलाओं का सशक्तिकरण और उनका राजनीतिक उठान पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। इतनी कटु आलोचना इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वे दूसरे गुट से हैं।

उन्हें इस आधार पर अयोग्य ठहराने की कोशिश का प्रतिकार किया जाना चाहिए। इसी रवैये को हम महिलाओं के

सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता में कमी और सिद्धांतों के विपरीत ठहरा सकते हैं। आने वाले वर्षों में भारत में और भी महिलाएं विधानसभाओं और संसद में जाएँगी। कुछ मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और शायद प्रधानमंत्री भी बनेंगी।

उनसे असहमति भी होगी, लेकिन उन्हें यह बार-बार यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वे उन पदों पर बैठने की हकदार हैं। क्योंकि वे महिलाएँ हैं। अगर हम मानते हैं कि महिलाएँ सत्ता की राजनीतिक में ज्यादा हिस्सेदारी की हकदार हैं, तो उन्हें एक बेहतर शासक के रूप में हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा। महिला के प्रति सम्मान ऐच्छिक नहीं हो सकता है।

महिला आरक्षण अधिनियम की तात्किक परिणति भी यही है। महिलाओं का सशक्तिकरण मतदान केंद्र से शुरू होकर शशथ ग्रहण समारोह पर खतम नहीं हो सकता। अफसोस की बात तो यह है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, अब वही कांग्रेस की नेता विपक्ष में होने के कारण महिला नेत्रियों पर ही चुनिंदा रूप से लगातार व्यक्तिगत हमले कर रही हैं। कांग्रेस लगातार एनसीपी की नेता सुनेत्रा के खिलाफ नकारात्मक खबरें फैलाने में लगी है।

यह दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण के प्रति कांग्रेस की कितनी प्रतिबद्धता है। इस समय डीएमके और एन सी पी (शरद पवार) के भी बीजेपी के करीब आने की खबरें चल रही हैं। क्या सिर्फ इस लिए सुनेत्रा पवार पर तो हमले नहीं किये जा रहे हैं कि उनकी जगह कोई आए लेने का मंसूबा बना रहा है। अगर ऐसा है तो महिला सशक्तिकरण के लिए इन पार्टियों को कोई प्रतिबद्धता नहीं है।

पेपर लीक बहस के दौरान विपक्षी दलों ने खोया सुनहरा अवसर

मृत्युंजय दीक्षित

केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार होने वाली पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से ध्वनिमत से करा लिया। इस विधेयक पर बहस के दौरान यह बात स्पष्ट हो गई कि विरोधी दल छात्र हिस्तेपी बनने का केवल दिखावा कर रहे थे। उनका वास्तविक उद्देश्य छात्रों के नाम पर संसदीय कामकाज को लटकाना, भटकाना व अटकाना ही था। कांग्रेस सहित विरोधी दलों के सांसदों ने पेपरलीक के मुद्दे पर केवल हंगामा और ओछी व गलत बयानबाजी ही करी। लोकसभा की बहस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष द्वारा छात्र आंदोलन की आड़ में देश को अराजकता की आग में झोंक कर उसमें अपनी राजनीतिक रोटिया सेंकने के सपने को चूर चूर कर दिया है। बहस के दौरान राजग गठबंधन के सांसदों ने स्पष्ट कर दिया कि पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम एनडीए सरकार में ही होगा जबकि विरोधी दल पूरी तरह से दिशाहीन और विभाजित दिखाई दिए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष को तथ्यों, तर्कों व आंकड़ों से बेअसर व हताश कर दिया।

अपनी आदत से मजबूर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने सदन के पटल पर गलत आंकड़े रखे। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स में शामिल डॉ वी. कामकोटि को गौ-मूत्र विशेषज्ञ



कहकर उनका उपहास उड़ाया। वी. कामकोटि के 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। प्रियंका गांधी को इस बात का न केवल संसद वरन सोशल मीडिया पर भी करारा जवाब मिला। कांग्रेस को इस बात का भी दर्द हो रहा होगा कि आधार के डिजाइनर नंदन नीलेकणि जो कभी कांग्रेस के साथ थे और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़े थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़े हैं।

कांग्रेस की बहस में रही सही धार राहुल गांधी ने संसद में इडिथट और अंधभक्त भक्त जैसे अमर्यादित शब्दों का उपयोग करके कुंद कर दी और बता दिया कि अब यह मुद्दा उनके हाथ से जा चुका है। उन्होंने दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर गोली चलने का झूठा दावा किया और गुहमंत्री अमित शाह पर हमलावर हो गए। उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि छात्र आंदोलन के दौरान गुह मंत्री विदेश चले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गुहमंत्री के कार्फिले में तीस गाड़ियाँ हैं। राहुल गांधी का पूरा बयान

हताशा और निराशा से भरा हुआ और झूठ का पुलिंदा मात्र था। राहुल गाँधी हमेशा की तरह बहस के बजाए नौटंकी करते दिखे। खुले माइक पर माइक बंद होने का आरोप लगाया।

उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना मुद्दा ही बदल दिया और चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाने लगे। सपा मुखिया ने कहा कि जो लोग मंदिरों में चढ़ावा चोरी नहीं रोक सकते वह पेपर लीक क्या रोक पाएंगे। बहस के दौरान इंडी गठबंधन के सभी सांसद कुठित नजर आ रहे थे।

एनडीए सांसदों ने पूरी तैयारी के साथ बहस में भाग लेकर विरोधियो व उनकी रणनीति को बेनकाब किया। विधेयक प्रस्तुत करते समय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2014 के मूड पेपर लीक जैसी तमाम घटनाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा और फिर बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या से लेकर अनुराग ठाकुर तक ने अपने तथ्यों से विपक्ष की पोल खोल दी। सदन में सरकार की ओर से बताया गया कि परीक्षा को लेकर देश प्रदेशों में तरह-तरह की घटनाएं होती रही हैं

जिनमें पेपर लीक भी है। यह एक प्रदेश या एक सरकार तक सीमित नहीं है। 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा, बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा, 2011 में आल इंडिया एट्रेस एजाम, 2012 में एम्स दिल्ली का पेपर लीक, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक, 2023 में महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा पेपर लीक जैसी घटनाएं घटीं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2014 के पूर्व यूपीए-2 के शासनकाल में 22 बार पेपर लीक की घटनाएं हुईं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार, बंगाल में टीएमसी, यूपी में सपा के शासनकाल में तो नकल माफिया का महामंत्र ही विकसित हो गया था। भौगोलिकसंदर्भ

अब बिल लोकसभा से पास हो चुका है, इंडी गठबंधन के नेताओं को जो कहना है जो आरोप लगाना है लगाते रहें अन्ततः नया कानून ही सच्चाई होगी। छात्रों के नाम पर बनी सीजेपी भी बेनकाब हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 2000 से अधिक अपराधियों की जंतर मंतर पर उपस्थिति चिह्नित की है। छात्रों को ध्यान रखना होगा कि 1973 से लेकर 1984 तक विभिन्न छात्र आंदोलनों के दौरान कम से कम 800 छात्रों की पुलिस की गोली व लाठी से मौत हुई थी तब देश में कांग्रेस की सरकारें ही थी। गांधी परिवार परिवार छात्र आंदोलन की आड़ में केवल अपनी वंशवादी राजनीति को धार देने और देश की जनता को भ्रमित व अराजकता की आग में झोकने का काम कर रहा है।

प्रियंका द्वारा गौमूत्र का उपहास कांग्रेस की हिन्दू विरोधी मानसिकता

राकेश सैन

कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी की योग्यता का जिक्र करते हुए अकसर राजनीतिक विश्लेषक एक बात का अवश्य जिक्र करते हैं कि उनकी छवि, विशेषकर नाक अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलती है। लेकिन अब दोनों दादी-पोतियों का एक और समान गुण सामने आया है, इंदिरा गांधी ने 7 नवम्बर, 1966 को संसद भवन के सामने हजारों गोभकों पर गोलियां चलवाई थी और लगभग उसी मानसिकता का परिचय देते हुए अब प्रियंका वाड़ा गांधी ने संसद के भीतर गौमूत्र का उपहास उड़ाया है। शर्मनाक बात है कि जब प्रियंका इस तरह का दुष्कर्म कर रही थी तो विपक्षी बेंचों पर बैठे कांग्रेसी सांसद भी खिलखिला रहे थे। हिन्दू विरोध से उपजी कांग्रेसियों की यह हंसी कौरवसभा में द्रौपदी चौरहरण के समय कपटी दुर्गोंपर भी लगाए गए अट्टहास की तरह हर हिन्दू के मनों को बौंध गई। संसद में मंगलवार को उस समय काफी हंगामा मचा जब प्रियंका वाड़ा ने पेपर लीक मामले पर सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में शामिल एक सदस्य की योग्यता उनके गौमूत्र विशेषज्ञ होने को बताई। लोकसभा में शिक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक को लेकर गठित उच्च स्तरीय कार्यबल पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी शामिल हैं। हालांकि चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन उनका इशारा आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामाकोटि की ओर माना जा रहा है, जो इंफोसिस के सह-संस्थापक निंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली इस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। 2025 में प्रो. कामाकोटि ने दावा किया था कि गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और पाचन संबंधी गुण होते हैं। प्रो. वी. कामकोटि देश के जाने-माने वैज्ञानिक हैं। जनवरी, 2025 को चेन्नई की एक गोशाला में माटू पोंगल कार्यक्रम में बोलेते हुए, कामकोटि ने देशी गाय और जैविक खेती के बारे में कहा। इस दौरान उन्होंने बताया कि गाय के मूत्र में जीवाणुरोधी, कवकरोधी और पाचन सम्बन्धी गुण होते हैं। उन्होंने एक तपस्वी से जुड़ी कहानी भी साझा की, जिन्होंने गौमूत्र पीकर अपना बुखार ठीक कर लिया था। इस ब्यान के

कारण उस समय भी प्रो. कामकोटि वामपंथी व जिहादी ताकतों के निशाने पर आ गए थे और प्रियंका ने भी अब उन जख्मों को पुनः कुरेद दिया है। गौमूत्र का उपहास उड़ाने वालों को जानना चाहिए कि हिन्दू धर्म में कोई भी विश्वास अवैज्ञानिक नहीं हैं, गौमूत्र के औषधीय गुण विज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं। भारत के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नागपुर के गोविन्धान अनुसंधान केंद्र के सहयोग से किए गए शोध पर आधारित गौमूत्र के गुणों को अमेरिकी पेटेंट मिल चुका है। गौमूत्र के अर्क पर पहला महत्वपूर्ण अमेरिकी पेटेंट (नंबर 6410059) एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाओं के असर को बढ़ाने के लिए 2002 में मिला था। इसके बाद कैसर रोधी दवाओं के प्रभाव को तेज करने और डीएनए सुरक्षा से जुड़े अन्य पेटेंट (पेटेंट नंबर 6896907 और 7718360) भी संयुक्त रूप से भारत के शोधकर्ताओं द्वारा अमेरिका में दर्ज कराए गए। गौमूत्र व अन्य प्राकृतिक चीजों से बने कीटनाशकों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और पेटेंट प्राप्त हुआ है। आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपाद येसो नाइक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुसार, इसकी घटक प्रयोगशाला, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान (सीआईएमएपी), लखनऊ ने नागपुर के गो-विज्ञान अनुसंधान केंद्र के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में गाय के मूत्र के आसवन (कामपेठ अर्क) का एक नया उपयोग खोजा है। यह आसवन संक्रमणरोधी और कैसररोधी एजेंटों सहित जैवसुरक्षित अनुपौष की सकिधता बढ़ाने और उपलब्धता को सुगम बनाने में सहायक है। गाय के मूत्र के आसवन में कैसररोधी प्राकृतिक एजेंट टैक्सोल (पैक्लिटेक्सेल) की जैव-संवर्धन क्षमता पाई गई है, जो यू वृक्ष (टैक्सस एसपीपी.) द्वारा सूक्ष्म मात्रा में उत्पादित होता है। गाय के मूत्र का आसवन, जीवाणुओं पर विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं की निष्फलता क्षमता बढ़ाने के अलावा, स्तन कैसर कोशिका लाइन एमसीएफ-7 के विरुद्ध पैक्लिटेक्सेल की कोशिका विभाजन अवरोधक गतिविधि को भी बढ़ा सकता है।

यदि हो गए हों पाप तो ऐसे करें पुण्य अर्जित

फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इस वर्ष यह एकादशी 19 मार्च शनिवार के दिन है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास बैठ कर भगवान का पूजन किया जाता है।

व्रत की कथा
एक बार एक राजा के राज्य में रात भर भूखा-प्यासा बैठा रहा। उस दिन फाल्गुन शुक्ल एकादशी थी। इस प्रकार अनजाने में ही उसने आमलकी एकादशी का व्रत रख लिया। रात्रि जागरण करने के कारण उसे अनजाने में ही इस व्रत का फल मिल गया। दूसरे जन्म में वह एख बड़े राज्य का अधिकारी बना। इसलिए लोग इस व्रत को करते हैं ताकि उनके पुनर्जन्म में वह और भी अधिक प्रभावशाली बन पाएं। दरअसल इस व्रत को करने से इस जन्म में किए पाप से मुक्ति मिल जाती है। और ईसान अगले जन्म में वैभव, सुख शांति के साथ जीताहै।

गोस्वामी तुलसीदास भी सत्संगति के महत्व को इस कथन में स्पष्ट करते हैं। एक घड आधी घडी, आधी की पुनि आध। तुलसी संगत साधु की, कटै कोटि अपराध।।

किस तरह मनी प्लांट अगर शुभ है तो अशुभ भी

मनी प्लांट यानि धन का पौधा। यह जितना हरा होता है घर में धन का आगमन उसी तेजी से होता है। इसके पत्तों का मुरझाना या सफेद हो जाना अशुभ है। मनी प्लांट जैसा कि नाम से ही जाहिर है मनी प्लांट यानि धन का पौधा। यह पौधा जितना हरा होता है घर में धन का आगमन उसी तेजी से होता है। इसके पत्तों का मुरझाना या सफेद हो जाना अशुभ माना जाता है। भूमि पर फैलकर वृद्धि करने वाली बेल दोषकारक होती है।

वैसे तो घर में रखने के लिए आपको पॉम लीव्स, बोनसाई जैसे कई इंडोर प्लांट मिल जाएंगे, लेकिन कम खर्च और अच्छी ग्रोथ के कारण जो रंग

हैं। लेकिन कई बार मनी प्लांट लगाने के बावजूद भी धनागमन में कई अंतर नहीं होता बल्कि और आर्थिक नुकसान उठाना पडता है। इसका कारण हे गलत दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर पौधे के लिए एक दिशा निर्धारित होती है। यदि पौधे को उचित दिशा में लगाया गया तो वह सकारात्मक प्रभाव डालता है वहीं, यदि उसके उस पौधे का गलत स्थिति में वृक्षारोपण किया गया तो वह नकारात्मक प्रभाव डालता है जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान होने लगता है।

वास्तु के अनुसार, यदि सही दिशा और सही जगह में मनी प्लांट का

मनी प्लांट यानि धन का पौधा। यह जितना हरा होता है घर में धन का आगमन उसी तेजी से होता है। इसके पत्तों का मुरझाना या सफेद हो जाना अशुभ है। यह पौधा जितना हरा होता है घर में धन का आगमन उसी तेजी से होता है। इसके पत्तों का मुरझाना या सफेद हो जाना अशुभ माना जाता है।

मनी प्लांट आपके घर में भरता है, वह किसी अन्य इंडोर प्लांट से संभव नहीं। इस प्लांट को लेकर लोगों के मन में कई तरह की धारणाएँ हैं, जैसे- इस पौधे को घर में लगाने से घर में पैसा आता है, तो कुछ का मानना है कि इस पौधे को लगाने से घरवालों की तरक्की होती है।

उसी मान्यता है कि जिसके घर में मनी प्लांट का पौधा लगा होता है उसके उसके घर में न केवल सुख-समृद्धि में इजाफा होता है बल्कि घर में धन का भी आगमन होता है। इसी वजह से कुछ लोग घरों में मनी प्लांट का पौधा लगाते

पौधा नहीं लगाया गया तो धनलाभ के बजाय हानि का सामना करना पडता है। वास्तु शास्त्रीयों का मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। मनी प्लांट को आग्नेय यानि दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाने का कारण ये है इस दिशा के देवता गणेशजी है जबकि प्रतिनिधि शुक्र हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं जबकि शुक्र सुख-

घर में समृद्धि लाएंगे ये उपाय



कडी मेहनत और प्रयासों के बावजूद जब समृद्धि आपसे दूर रहती है तो अपने घर के वास्तु पर ध्यान देना चाहिए। यह संभावित है कि आपकी समृद्धि की राह की रुकावट के लिए घर का वास्तु जिम्मेदार हो। अगर घर में वास्तु दोष है तो आप कुछ आसान उपायों के जरिए उन्हें दूर करके संपन्नता की राह की रुकावट को दूर कर सकते हैं।

तिजोरी की दिशा :
अपने घर में तिजोरी को हमेशा दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दीवार के करीब या इस दीवार की अलमारी में रखना चाहिए। इस दिशा में तिजोरी होगी तो वह हमेशा उत्तर दिशा में खुलेगी। उत्तर भगवान कुबेर की दिशा है और

उस दिशा में तिजोरी खुलने का अर्थ यही है कि धन के देव कुबेर उसे भरते रहेंगे। तिजोरी या धन की अलमारी को किसी भी अन्य दिशा में रखने से बचें।
तिजोरी बीम के नीचे न हो:
किसी भी हाल में धन या तिजोरी बीम के नीचे न हो। ऐसी स्थिति में



मनोकामनाएं सिद्ध करने हेतु विशेष गणेश मन्त्र

भगवान गणेश जी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते है। उनकी उपासना बहुत ही सरल है और वह अपने भक्तो पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते है। शास्त्रों में अलग अलग मनोकामनाओ के लिए गणेश जी के कई सिद्ध मन्त्र दिए हुए है । जिनका यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के जाप किया जाय तो शीघ्र ही अभीष्ट लाभ की प्राप्ति होती है । गणेश उत्सव के इन 10 दिनों में अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने हेतु कार्यविशेष के मंत्रो का जाप करना विशेष फलदायी रहता है ।

समृद्धि लाने वाले। यही नहीं बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र को माना गया है। इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। मनी प्लांट को कभी भी ईशान यानि उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, यह दिशा इसके लिए सबसे नकारात्मक मानी गई है। क्योंकि ईशान दिशा का प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। और शक्र तथा बृहस्पति में शत्रुवत संबंध होता है। इसलिए शुक्र से संबंधित यह पौधा ईशान दिशा में होने पर नुकसान होता है। हालांकि इस दिशा में तुलसी का लगाया जा सकता है। घरों का सुंदरता बढ़ाने के लिये मनी प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये शुक्र के कारक हैं। मनी प्लांट लगाने से पति-पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। फँगशुई के अनुसार बांस के पौधे सुख व समृद्धि के प्रतीक होते हैं मनी प्लांट की सबसे बडी खासियत यह है कि घर हो या आँगन यह प्लांट कहीं भी आसानी से लग जाता है। साथ ही यह

केवल पानी में भी लगाया जा सकता है और इसके रखरखाव के लिए भी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पडती है। इसे घर के अंदर व बाहर दोनों जगह ही रखा जा सकता है।

मनी प्लांट ऐसी जगह रखें जहां अधिक धूप ना हो। इसे घर में भी रखा जा सकता है। पानी में रखना बेहतर होता है लेकिन इस पानी को हर सप्ताह बदल देना चाहिए। जमीन पर इसकी बेलों को नहीं फैलाना चाहिए। मनी प्लांट को घर के अंदर गमले में अथवा बोतल में पानी भरकर भी लगाया जा सकता है। इससे सुख-समृद्धि प्रदान करने वाले सकारात्मक उर्जा को आकर्षित किया जा सकता है। जिस कोने में यह होता है उसकी ओर बरबस ही निगाहें चली जाती हैं।

आप चाहें तो इसकी इन सुनहरी पत्तियों को काँट-छाँट कर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में मनीप्लांट लगाने पर सुख-समृद्धि के साथ धन का आगमन बढ़ता है। इसी के चलते लोग अपने घरों में यह पौधा लगाते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में नहीं लगाया गया है तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए शुक्र से संबंधित यह पौधा ईशान दिशा में होने पर नुकसान होता है। हालांकि इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है।

न गिरे।

गोलाई से बचें :

उत्तर-पूर्व कोने में घुमावदार दीवार के निर्माण से बचना चाहिए। इस दिशा में अगर बाउंड्री वॉल भी बनवा रहे हैं तो उसमें गोलाई न हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसे सही कोण पर मोड़ देने के बारे में सतर्क रहें।

छत की ढलान की दिशा:

छत में हमेशा ढलान दक्षिण पश्चिम से उत्तर-पूर्व की तरफहोना चाहिए। घर बनाने समय इस बात का ध्यान रहे कि छत का उत्तर-पश्चिम हिस्सा थोडा सा ऊंचा हो।



गणेशजी के इन नामों व इन मंत्रो कै जाप से किसी भी प्रकार के कार्यों की अडचने दूर हो जाती है

भगवान गणेश के अति शुभ बारह नामों का नित्य स्मरण करने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पडता है ।विद्या अध्ययन, विवाह के समय, यात्रा , रोजगार के शुभारम्भ में या अन्य किसी भी शुभ कार्य को करते समय गणेश के बारह नाम लेने से कार्यों की अडचने दूर हो जाती है।

ऋण से मुक्ति के लिए
“ॐ गणेश ऋणां छिन्धि वरणयं हुं नमः फट”
इस मन्त्र की एक माला का नित्य जाप करें।
संकट नाश के लिए
“ॐ नमो हेरम्ब मदमोहित मम संकटान निवारय स्वाहा”
इस मन्त्र की 1 माला का नित्य जाप करें।
वशीकरण के लिए
“ॐ श्रीं गं सौम्याय गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा”
निम्न मंत्र की 5 माला का जाप करें।
आलस्य, निराशा, कलह व विपत्ति नाश के लिए

“गं क्षिप्रप्रसादनाय नमः”
मन्त्र की कम से 2 माला का जाप करें।
धन व आत्मबल प्राप्ति के लिए
“ॐ गं नमः”
निम्न मन्त्र की एक माला का नित्य जाप करें।
आर्थिक समृद्धि व रोजगार प्राप्ति के लिए
“ॐ श्रीं गं सौभ्याय गणपते वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा”
इस मंत्र की एक माला का नित्य जाप करें।
सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिये
“गं गणपते नमः”
इस मंत्र की एक माला का नित्य जाप करें।

सुबह उठते ही सबसे पहले क्या और क्यों देखें



प्रतिदिन सुबह-सुबह हमारा एक प्रश्न होता है कि हमारा दिन कैसा रहेगा दिन को अच्छा बनाने के लिए सभी कुछ न कुछ धर्म-कर्म अवश्य ही करते हैं। सभी चाहते हैं कि उनका नया दिन शुभ रहे, खुशियां देने वाला हो, दुःख दूर करने वाला हो और सफलताएं दिलाने वाला हो।

शास्त्रों के अनुसार एक सटीक उपाय बताया गया है जिससे हमारा पूरा दिन श्रेष्ठ बनता है और सभी दुःख-क्लेश दूर होते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारा पूरा दिन अच्छा रहे और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहे। कई लोग भगवान के दर्शन करते हैं तो कुछ अपने घर के सदस्यों का चेहरा देखते हैं लेकिन बिस्तर छोड़ने से पहले हमें हमारे हाथों के दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हाथों के दर्शन से क्या होगा।

तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि धर्म ग्रंथों और ऋषि-मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवीय शक्तियां निवास करती हैं। इसी वजह से हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। दोनों हाथों को मिलाकर उसके दर्शन करके ही बिस्तर छोड़ना चाहिए। हमारे हाथ के आगे के हिस्से में (अंगुलियों की ओर) लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और नीचले भाग में नारायण यानी विष्णु का वास होता है। प्रातः हाथों के दर्शन से ही तीनों दिव्य शक्तियों के दर्शन का पुण्य मिलता है।

सुबह हथेलियों का दर्शन करने के पीछे यही संदेश है कि हम परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमें हाथों के जरिए ही मिलता है। इसलिए हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु तीनों का वास माना गया है। कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। इसके

लिए जरूरी है कि सुबह उठकर ऐसे काम करें जो आपको उत्साहित और उर्जावान बनाए रखे। न कि ऐसी गलती कर बैठें कि पूरा दिन तनाव और परेशानी में बीते।

हथेली को देखें-
हथेली को देखें, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपना दिन बेहतरीन बनाने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले अपना हाथ देखना चाहिए। हाथ ही कर्म करता है और भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है।
आखिर क्यों देखें हथेली-
आखिर क्यों देखें हथेली, कहा जाता है कराप्रे वसति लक्ष्मीः, कर मध्ये सरस्वती। करमूले त् गोविन्दः, प्रभाते कर दर्शनम। यानी हथेली में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का वास है। इनके दर्शन से पूरा दिन अच्छ रहता है।

मन्त्र का ध्यान
मन्त्र का ध्यान, हथेली देखते हुए इस मंत्र का ध्यान भी करना चाहिए, ताकि आपके मन में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद की छवि बने।
सबसे पहले किसे छुयें-
सबसे पहले किसे छुयें, बिछावना से उतरते समय पांव सीधे जमीन पर में नहीं रखना चाहिए। धरती को माता के समान आदरणीय कहा गया है इसलिए सबसे पहले धरती का स्पर्श करके हथेली को माथे से लगाएं।

ऊर्जा का संचार-
ऊर्जा का संचार, ऐसे करने से तन मन में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। अपने कार्य में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।

स्त्री शक्ति है ‘यिन’ और ‘यांग’ ?

चीनी फेंगशुई के अनुसार, यिन और यांग शक्ति सृष्टि में शांति स्थापित करने के लिए होती हैं। ये एक दूसरे की पूरक होती हैं। लेकिन कभी-कभी ये एक दूसरे की विरोधी भी हो सकती हैं। इनमें एक के बिना दूसरे के अस्तित्व नहीं हैं।

‘यिन’ स्त्री शक्ति है जो अंधकारमय और एवं निष्क्रिय होती है। ‘यांग’ पुरुष शक्ति है जो प्रकाशमय और सक्रिय है।

सृष्टि में एकरसता होती है। उदाहरण के लिए सूर्य को तेज रोशनी यांग होती है। लेकिन इसे परदे लगाकर कम किया जाए या संतुलित किया जा सकता है।

ये हैं यिन शक्तियां
पृथ्वी, चंद्रमा, रात, अंधकार, नीचे, ठंडा, मुलायम, निष्क्रिय, पानी, पीछे, पुत्री और मां।
ये हैं यांग शक्तियां
आकाश, सूर्य, दिन, प्रकाश, ऊपर, गरम, कठोर, पिता, पुत्र, आगे, आग और सक्रिय।

मुस्लिम नहीं कर सकेंगे एक से ज्यादा शादी? बहुविवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें मुस्लिमों के बीच बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिमों में बहुविवाह संविधान के प्रविधानों का उल्लंघन करता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची और वी.मोहन की पीठ ने महिलाओं के अधिकारों की कार्यकर्ता जाकिया सोमन और नूरजहां सफिया नियाज सहित अन्य द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 को लागू करने का निर्देश मांगा गया है, जो बहुविवाह को समान रूप से दंडित करती है और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत किसी भी छूट को हटाने की मांग करती है। इसमें केंद्र से बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए विधायी कदम उठाने और इसे सभी नागरिकों के लिए प्रारंभ से ही अमान्य मानने का निर्देश देने की मांग की गई है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।

देश में बिछेगा 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का जाल

नई दिल्ली। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अभी शुरू भी नहीं हुई है और देश पहले ही सात अन्य कॉरिडोर की योजना बना रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में लगभग 4,000 किलोमीटर के नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की थी. केंद्र सरकार अब इन सभी सात रूटों का निर्माण तेजी से, कम लागत में और बेहतर ढंग से करने के लिए एक मानक डिजाइन तैयार कर रही है. भारत में प्रस्तावित सात नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी, देश के उत्तर-पश्चिम से लेकर उत्तर-पूर्व तक फैली लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी दूरी को कवर करते हुए प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगे.इन कॉरिडोरों के बनने से यात्रा के समय में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जहां मुंबई से पुणे का सफर महज 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 1 घंटा 55 मिनट में सफर करेगी।

भारत की ओर चीन ने ताने 12 फाइटर?

नईदिल्ली। दो सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि होटन एयरबेस पर टरमेक पर आठ J-20 माइटी ड्रैगन स्टील्थ फाइटर खड़े देखे गए, जबकि तिब्बत के ल्हासा इलाके में डैम्सुंग एयरबेस पर चार छ-20 तैनात थे. कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरों से भारत के खिलाफ चीन के खतरनाक इरादों का पता चला है. सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास दो एयरबेस पर अपने कम से कम 12 सबसे एडवांस्ड J-20 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात किए हैं. हाल के वर्षों में लाइन ऑफ़ एक्जुअल कंट्रोल के पास पांचवीं पीढ़ी के इन लड़ाकू विमानों की यह अब तक की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है. कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी वैंटोर द्वारा ली गई और इंडिया टुडे के साथ शेयर की गई इन तस्वीरों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फ़ोर्स को शिनजियांग के होटन एयरबेस और तिब्बत के डैम्सुंग एयरबेस पर इन विमानों को तैनात करते हुए देखा जा सकता है।

बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नईदिल्ली। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच अब इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के. गैर-विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए संविधान में छह महीने की छूट दी गई है, लेकिन ये छूट केवल एक बार के लिए होती है. दीपक प्रकाश इस समयसीमा को पार कर चुके हैं. वहीं, बिहार सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि ये मामला पहले से ही 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा, राज्य सरकार उसका पालन करेगी. इस पर सोजेआई ने कहा कि ये पची तरह कानून का सवाल है. राज्य सरकार को बताना होगा कि कोई व्यक्ति बिना विधायक/विधान परिषद का सदस्य बने छह महीने से ज्यादा वक्त तक मंत्री कैसे बना रह सकता है।

कुवैत में चीनी फर्म पर ईरानी हमला

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने गुरुवार तड़के कुवैत में हमला किया, जिसमें एक चीनी कंपनी की इमारत निशाना बनी. कुवैती सेना के अनुसार, उत्तरी कुवैत स्थित इमारत हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एक कर्मचारी की मौत हो गई. मृतक कर्मचारी नेपाल का नागरिक बताया जा रहा है. यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब जॉर्डन की एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई पांच मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया. उधर, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों का एक बड़ा दौर पूरा कर लिया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड फ़ोर्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया. इनमें सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, साथ ही तटीय निगरानी एवं रक्षा ठिकाने शामिल हैं.अमेरिका के अनुसार, यह कार्रवाई जॉर्डन में स्थित उसके सैन्य अड्डे पर ईरान के पहले किए गए मिसाइल हमले के जवाब में की गई है. क्षेत्र में लगातार बढ़ते सैन्य टकराव के बीच हालिया घटनाओं ने पश्चिम एशिया में तनाव को और गहरा कर दिया है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पास

नई दिल्ली। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के मंजूरी दी, राज्यसभा में यह बीते 29 जुलाई को पारित हुआ था। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक बुधवार को लोकसभा में किया था।

लोकसभा ने शुक्रवार को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। राज्यसभा में बीते 29 जुलाई को यह विधेयक पारित किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित करने के लिए पेश किया।

इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए।

बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके।

मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की



देरी से कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते थे कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर यह नहीं कहना चाहिए कि बिना चर्चा के क्यों पारित किया।

रीजीजू ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता आपसे जवाब मांगेगी। अब आप बाहर जाकर यह आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है। आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें।

पीठासीन सभापति दिलीप सैंकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि

सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा। यह सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर सैंकिया ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगि कर दी।

विपक्षी सदस्य प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ लाए गए लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे।

हालाँकि, कोई विपक्ष सदस्य नहीं बोला और इसके बाद नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके।

मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

सैंसेक्स 166 अंक चढ़ा निफ्टी 24,384 पर बंद

नईदिल्ली। चरेलू शेयर बाजार ने शुक्रवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। ऑटो और वित्तीय सेवा शेयरों में खरीदारी के दम पर प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 166.49 अंक यानी 0.21 फीसदी की बढ़त के साथ 78,094.64 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 50 66.45 अंक यानी 0.27 फीसदी चढ़कर 24,383.60 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और जियो फाइर्नेशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयर रहे। इन शेयरों में मजबूत खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। बाजार की व्यापक तस्वीर भी सकारात्मक रही। निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप दोनों इंडेक्स 0.44 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे निवेशकों की व्यापक हिस्सेदारी देखने को मिली।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा 9 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में नौ प्रतिशत बढ़कर 1,488 करोड़ रुपए हो गया। एलआईसी द्वारा प्रवर्तित इस आवास वित्त कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 1,360 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया था। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी की कुल आय जून तिमाही में घटकर 7,066 करोड़ रुपए रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7,233 करोड़ रुपए थी। कंपनी की ब्याज आय भी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 7,024 करोड़ रुपए रह गई, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 7,113 करोड़ रुपए थी। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का कुल खर्च घटकर 5,177 करोड़ रुपए रह गया।

यूरोप में डीजल संकट गहराया रिलायंस ने बढ़ाया एक्सपोर्ट

नईदिल्ली। यूरोप में डीजल की भारी कमी और रूस के निर्यात पर रोक के बीच भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जुलाई में यूरोप और ब्राजील को डीजल का निर्यात बढ़ा दिया है। इससे वैश्विक बाजार में डीजल की सप्लाई को कुछ राहत मिल सकती है। अमेरिका-ईरान युद्ध और रूस के निर्यात प्रतिबंध की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में डीजल की उपलब्धता पर दबाव बना हुआ है। यूरोप में डीजल का स्टॉक 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से खाड़ी देशों से यूरोप को होने वाली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। इसका असर यह हुआ कि यूरोप में डीजल का मुनाफा (मार्जिन) बढ़कर रिकॉर्ड 74 डॉलर प्रति बैरेल तक पहुंच गया। शिप ट्रेडिंग डेटा के मुताबिक, रिलायंस ने जुलाई में अपने जामनगर रिफाइनरी से करीब 40 लाख से 50 लाख बैरेल डीजल यूरोप भेजा।

विदेशों में बढ़ रहा भारतीय कंपनियों का निवेश

नईदिल्ली। भारत में आने वाले विदेशी निवेश की खूब चर्चा होती है, लेकिन अब भारतीय कंपनियां भी तेजी से विदेशों में निवेश बढ़ा रही हैं। हालाँकि जून 2026 में विदेशों में भारतीय कंपनियों का निवेश पिछले साल के मुकाबले घटा है, लेकिन पिछले 10 साल का ट्रेंड बताता है कि भारतीय कंपनियों की वैश्विक मौजूदगी लगातार मजबूत हो रही है। खास बात यह है कि अब सिर्फ वित्तीय कंपनियां ही नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन, फार्मा और मैनुफैक्चरिंग जैसे सेक्टर भी विदेशों में निवेश बढ़ा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 में भारतीय कंपनियों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश घटकर 2.99 अरब डॉलर रह गया। एक साल पहले जून 2025 में यह 5.03 अरब डॉलर था। यानी सालाना आधार पर इसमें करीब 40.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

खेल प्रमुख समाचार

शान मसूद वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर

पोर्ट ऑफ स्पेन। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे

टेस्ट से पूर्व पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अनुभवी बल्लेबाज शान मसूद रविवार से शुरू होने

वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उन्हें तारोबा में सीरीज के पहले मैच के दौरान बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। मसूद को यह चोट तब लगी जब त्रिनिदाद में पहले टेस्ट की पहली पारी में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स की एक तेज गेंद उनकी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगी। पाकिस्तान यह मैच 90 रन से हार गया था।

इस चोट के कारण मसूद न केवल क्रॉस पार्क ओवल में होने वाले दूसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच से बाहर हो गए हैं, बल्कि 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में उनके खेलने पर भी संदेह पैदा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान में कहा, पाकिस्तान के टेस्ट बल्लेबाज शान मसूद त्रिनिदाद की ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में पहले टेस्ट के दौरान बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चोट लगने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

उन्होंने आगे कहा, स्कैन और क्लिनिकल जांच के बाद शान का इलाज पाकिस्तान टीम का मेडिकल पैनल कर रहा है। लीड्स में 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में उनका खेलना उनके ठीक होने और क्लिनिकल प्रोग्रेस पर निर्भर करेगा। इस बीच वह टीम के साथ ही रहेंगे। पहले टेस्ट में खराब बल्लेबाजी के बाद पाकिस्तान के टेस्ट-टैंक के सामने अब मसूद की जगह भरने के लिए खिलाड़ियों के चयन की चुनौती है। अनुभवी जोड़ी अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील, जिन्हें पहले मैच से पहले पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण अब्दुल्ला फजल के बाहर होने के बाद टीम में शामिल किया गया था, अब फिर से चयन की दौड़ में हैं।

तमाल बंधोपाध्याय

एक प्रवासी भारतीय (एनआरआई) ग्राहक दो वर्ष बाद जब अपनी बैंक शाखा पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि उनकी एक टर्म डिपॉजिट पर 'लियन' लगा था यानी उन्हें रकम निकालने या इधर-उधर करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें यह देखकर काफी हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने इस डिपॉजिट को गिरवी रखकर कर्ज नहीं लिया था बल्कि उन्होंने उस बैंक से ही कभी कोई कर्ज नहीं लिया था।

लियन किसी ग्राहक के धन या संपत्ति पर किसी बैंक का कानूनी अधिकार होता है, जिसके जरिये कर्ज की अदायगी पक्की हो जाती है। बैंक खाते पर लियन लगा हो तो उसमें पड़ी रकम का एक हिस्सा कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। ग्राहक को खाते में वह रकम दिखाई तो देगी मगर वह उसे न तो निकाल सकता है, न ही कोई भेज सकता

है या खर्च कर सकता है।

छानबीन हुई तो उस प्रवासी ग्राहक के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह मामूली धोखाधड़ी नहीं थी बल्कि इसमें कई बैंकों से जुड़े आपराधिक सिंडिकेट का हाथ था, जिसने कर्मचारियों की मिलीभगत, जाली दस्तावेजों, फर्जी ऋण और रियल एस्टेट सौदों का जाल बुना था। पूरा खेल उन लोगों के टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की गुप्तचर चोरी पर टिका है, जो उसे मुश्किल से पकड़ पाएंगे जैसे सालों तक बाहर रहने वाले एनआरआई और डिजिटल बैंकिंग से नावाकिफ बुजुर्ग।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा 2026 की शुरुआत में राज्य सभा में पेश सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021 में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत वाले धोखाधड़ी के 2,624 मामले दर्ज किए गए थे, जिनकी संख्या वित्त वर्ष 2025 में घटकर



1,935 रह गई। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में ऐसे मामले और भी घटकर केवल 400 रह गए। लेकिन मामलों की संख्या घटने से यह पता नहीं चलता कि धोखाधड़ी कितनी पेचीदा है। आईआईएम बेंगलूरु के एक शोध पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि लगभग 34 प्रतिशत बैंकिंग धोखाधड़ी बैंक के कनिष्ठ और मध्य स्तर के कर्मचारी ही करते हैं। इससे बैंकों की ईमानदारी, विश्वसनीयता और प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े होते हैं।

एनआरआई के साथ हुई धोखाधड़ी इस

तरह की पहली घटना नहीं है। देश में कई जगहों पर वर्षों पर ऐसा होता रहा है। मगर इस फर्जीबाड़ी की शुरुआत कैसे होती है ?

सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच रखने वाला कोई कर्मचारी जाली कागज इस्तेमाल कर एनआरआई के टर्म डिपॉजिट के बदले कर्ज दिखाता है। टर्म डिपॉजिट की असली रसीद दी ही नहीं जाती। इससे प्रणाली में तो उस पर लियन रहता है मगर एनआरआई ग्राहक को पता नहीं चलता। इससे बाद एक शाखा दूसरी शाखा को बचाने आती है। एनआरआई के लौटने से पहले दूसरी शाखा में किसी और के टर्म डिपॉजिट पर एक और कर्ज लिया जाता है और उस पैसे से पहला कर्ज चुका दिया जाता है। इस तरह लियन हट जाता है, सबूत खत्म हो जाता है और दूसरे खाते से नई चेक बुक जारी कर दी जाती हैं, जिसकी जानकारी खाताधारक को नहीं होती।

आखिर में अपराधियों का सिंडिकेट

हरकत में आता है। शक होने पर जब कोई एनआरआई शिकायत करता है, आंतरिक जांच शुरू होती है और पैसे का लेनदेन पकड़ा जाता है तब पता चलता है कि कोई बेईमान कर्मचारी अकेले काम नहीं कर रहा था बल्कि एक ही शहर के कई बैंकों के कर्मचारी मिलकर एक दूसरे को बचाने के लिए धोखाधड़ी वाला ऋण एक जगह से दूसरी जगह घुमा रहे थे। ऋण का रकम आम तौर पर जायदाद के सौदों में इस्तेमाल की जाती है। शक होने पर जब ग्राहक पूछताछ करता है तो कोई नया कर्ज लेकर उसके खाते का ऋण खत्म कर दिया जाता है। ऐसी वारदात बैंक कारोबार में विश्वास का गलत फायदा उठाकर अंजाम दी जाती हैं। बैंक शाखाओं में कर्मचारी जमा का रीन्यूअल कर सकते हैं, एनआरआई व अन्य ग्राहकों की मदद कर सकते हैं और बुजुर्ग खाताधारकों के कागजात संचाल सकते हैं। उन पर नजर भी नहीं रखी जाती।

जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए

शासन की योजनाएं ला रही परिवर्तन: डॉ. रमन

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज शुक्रवार को पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में आयोजित श्रमिक सम्मलेन एवं श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 1802 हितग्राहियों को 3 करोड़ 43 लाख 74 हजार 970 रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में हस्तांतरित किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने अपने उद्घोषन में कहा कि श्रम विभाग की विभिन्न योजना अंतर्गत राजनांदगांव जिले के श्रमिक हितग्राहियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की गई है। प्रदेश की आबादी जिसमें 45 प्रतिशत हिस्सा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जिनके लिए शासन द्वारा विभिन्न



योजनाएं प्रारंभ की गई। जिसका उद्देश्य झुग्गी, झोपड़ी में रहने वाले, मेहनत करने वाले, ईंट-पत्थर उठाने वाले, सड़क, पुल-पुलिया एवं भवन निर्माण करने वाले, तैदूपत्ता संग्राहक, खेती-किसानी एवं मजदूरी करने वाले मेहनतकश श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शुरू की गई थी एवं सहायता राशि का प्रावधान किया गया था।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू, मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा

सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत राजनांदगांव में एक लाख 53 हजार 383 श्रमिक पंजीकृत है। वहीं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में एक लाख 18 हजार 608 श्रमिक पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की क्षमता एवं संभावनाओं से परिचित है। इसके अनुरूप जिले में श्रमिकों का पंजीयन एक वर्ष बाद दोगुना करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर श्रमिकों का पंजीयन बढ़ाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. राम प्रताप सिंह ने कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूरी के हित के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। लाखों परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्रमिक परिवारों को 886 करोड़ रूपए की सहायता

प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूरी के हित में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त निरुल्लूक शिक्षा प्रदान किया जाता है। श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं पात्र श्रमिक शासन की योजनाओं से वर्चित न हो इसके लिए लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा ने कहा कि राजनांदगांव जिले में श्रमिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है।

प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूरी के हित में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त निरुल्लूक शिक्षा प्रदान किया जाता है। श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं पात्र श्रमिक शासन की योजनाओं से वर्चित न हो इसके लिए लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा ने कहा कि राजनांदगांव जिले में श्रमिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे शासन की योजनाओं का लाभ: राज्यपाल डेका

रायपुर। प्रदेश के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अपने दो दिवसीय रायगढ़ प्रवास के प्रथम दिवस जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। जिला कलेक्टर डे में आयोजित बैठक में उन्होंने जल संरक्षण, पौधारोपण, पर्यावरण संवर्धन, जैविक



कृषि, स्वच्छता, योग, टीबी उन्मूलन, आजीविका, सहकारिता, सड़क सुरक्षा सहित बीस से अधिक बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ.सी.आर.प्रसन्ना, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। राज्यपाल श्री डेका ने जिले में जल

संरक्षण एवं जल संचयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेते हुए कहा कि वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अन्य राज्यों असम, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में जल संरक्षण के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए वर्षा जल संग्रहण, वाटर हार्वैस्टिंग तथा जल स्रोतों के संरक्षण के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पुराने कुओं, बावड़ियों तथा अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाया जाए, जिससे भू-जल स्तर में स्थायी सुधार हो सके।

सेवा, शिद्वत और संकल्प से करें काम : अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज बेमेतरा जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जिले के समग्र विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे सेवा, शिद्वत और संकल्प के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा बेमेतरा को विकास के हर क्षेत्र में प्रदेश का अग्रणी जिला बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि बेमेतरा भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अनुकूल जिला है, जहां बेहतर कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल, विधायक श्री दीपेश साहू और ईश्वर साहू तथा कलेक्टर श्रीमती



प्रतिष्ठा ममगाई भी बैठक में शामिल हुई।

उन्होंने कहा कि एक सफल अधिकारी वही होता है जो पूर्व नियोजित कार्ययोजना के साथ निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करता है। सभी अधिकारी जनसेवक की भावना से कार्य करते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें, स्वयं का नियमित मूल्यांकन करें तथा अपनी कमियों को दूर कर बेहतर परिणाम सुनिश्चित करें।

उप मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को

पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध कराने, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल संचयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत निर्मित योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर उनके सुचारु संचालन पर भी बल दिया। उन्होंने बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।

श्री साव ने जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं।

15 अगस्त को छत्तीसगढ़ में मनेगा उल्लास महा-चौपाल, स्वतंत्रता दिवस पर साक्षरता अभियान को मिलेगा नया आयाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2026-27 में प्रदेश के जनता को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राज्यभर में उल्लास महा-चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य साक्षरता को देशभक्ति से जोड़ना और 15 वर्ष से अधिक आयु के गैर-साक्षर वयस्कों को सशक्त बनाना है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रति सिंह तथा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक एवं सदस्य सचिव द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या ग्राम पंचायतों में साक्षरता नारों के साथ मोबाइल टॉर्च रैली तथा मशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें ज्ञान की मशाल शिक्षकों से होते हुए नव-साक्षरों के हाथों में सौंपी जाएगी। 15 अगस्त प्रातः 7 बजे ध्वजारोहण कर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और स्वयंसेवकों द्वारा साक्षरता संदेशों वाले प्ले-कार्ड्स के साथ प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके पश्चात् प्रातः 8 बजे गांव के बुजुर्ग नव-साक्षरों या नव-साक्षर महिलाओं द्वारा ध्वजारोहण कर सामूहिक उल्लास साक्षरता की शपथ ली जाएगी।

ध्वजारोहण के बाद आयोजित महा-चौपाल में नव-साक्षर अपने अनुभव साझा करेंगे तथा बुजुर्ग लोकगीत व कहानियां सुनाएंगे। मातृत्व साक्षरता के तहत बच्चे अपनी माताओं को मंच पर लाकर पहली बार पेन या चाँक से उनका नाम लिखना सिखाएंगे।सार्वजनिक स्थलों पर उल्लास की घंटी लगाई जाएगी जिसे साक्षर होने वाले व्यक्ति बजाएंगे। उल्लास दीवार पर नव-साक्षर अपने पहले हस्ताक्षर करेंगे। वहीं, सर्वाधिक असाक्षरों को साक्षर बनाने वाले युवाओं को सुपर 30 के तहत सम्मानित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री शर्मा की पहल पर कावड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन

रायपुर। पवित्र सावन माह के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा की पहल पर अमरकंटक स्थित मृत्युंजय आश्रम में कबीरधाम जिले सहित आसपास के कावड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है। सावन के पहले ही दिन 500 कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं ने मृत्युंजय आश्रम में प्रसादी ग्रहण किया। यह सेवा पूरे सावन माह तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सुबह की चाय और नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का निःशुल्क सात्विक भोजन, विश्राम स्थल, पेयजल, स्वच्छ शौचालय एवं प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

सेवा का संचालन उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जो कावड़ यात्रियों का पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत एवं सेवा



कर रही है। समिति के सदस्य लगातार यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सावन माह भगवान शिव की आराधना का महीना है और शिवभक्तों की सेवा करना वास्तव में शिव सेवा के समान है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा कठिन होती है और हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को इस यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपनी भक्ति पूर्ण कर सकें। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष लगभग 80 हजार से

अधिक श्रद्धालुओं ने इस सेवा का लाभ लिया था और इस वर्ष भी बड़ी संख्या में कावड़ यात्री अमरकंटक पहुँच रहे हैं। लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सेवा केंद्र की व्यवस्थाओं का विस्तार भी किया गया है, ताकि किसी भी भक्त को असुविधा न हो। मृत्युंजय आश्रम स्थित यह सेवा केंद्र ना केवल भक्ति, बल्कि समाज सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदना का एक अनूठा उदाहरण बन चुका है। असुविधा न हो और वे पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपनी भक्ति पूर्ण कर सकें। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष लगभग 80 हजार से

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं को और प्रभावी बनाएं: साहू

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने आज धमती स्थित %सखी वन स्टॉप सेंटर का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में पीड़ित महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा वहां के समस्त पंजियों (रजिस्ट्रें) एवं पत्रावलियों की बारीकी से जांच की अध्यक्ष डॉ. साहू ने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन पूर्ण निष्ठा के साथ 24x7 सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी समय सहायता के लिए पहुंचने वाली पीड़ित महिला को किसी प्रकार की असुविधा या विलंब का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सखी सेंटर की योजनाओं और हेल्पलाइन की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रमुख स्थानों पर सूचनात्मक डिस्प्ले व होर्डिंग्स लगाने, बढ़ते साइबर अपराधों से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस विभाग के उप पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित कर विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन करने तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु जिले के माननीय न्यायाधीशों एवं शासकीय अधिकारियों को आमंत्रित कर लोगल अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करने के निर्देश दिए।

मुस्कुराता बस्तर' थीम पर 3 अगस्त को कार्टून कार्यशाला

रायपुर। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के सहयोग से देश की एकमात्र मासिक कार्टून पत्रिका कार्टून वॉच द्वारा जागदलपुर में आगामी 3 अगस्त को स्कूली विद्यार्थियों के लिए 'मुस्कुराता बस्तर' थीम पर विशेष कार्टून कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को कार्टून और कैरिकेचर कला का प्रशिक्षण देने के साथ बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और लोकजीवन को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर आज विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों के कारण देश-दुनिया में नई पहचान बना रहा है। चित्रकोट और तीरथाढ़ जलप्रपात, कोंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर दशहरा तथा अन्य लोकपर्व बस्तर की समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं। कार्टून वॉच के संपादक श्री त्यंबक शर्मा ने बताया कि कार्यशाला की थीम 'मुस्कुराता बस्तर' इन्हीं सकारात्मक पहलुओं को कार्टून कला के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति देना है। इस कार्यशाला में दिल्ली के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट श्री माधव जोशी तथा पुणे के प्रसिद्ध कैरिकेचर कलाकार शुभम जिंदे लाइव डेमो के माध्यम से ऑन-द-स्पॉट कार्टून और कैरिकेचर बनाने का प्रशिक्षण देंगे। साथ ही विद्यार्थियों को कार्टून कला के सामाजिक, रचनात्मक और रोजगारपरक पक्षों से भी परिचित कराया जाएगा।

अमानक पनीर और डेयरी एनालॉग उत्पादों पर लगा प्रतिबंध

रायपुर। राज्य सरकार ने अमानक दुग्ध उत्पादों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ की पूरी सीमा में ऐसे डेयरी एनालॉग या गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जो असली दूध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 एवं 18 के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश में विशेष रूप से पनीर, क्रीम, मक्खन जैसे अमानकीकृत उत्पादों पर रोक लगायी गई है, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा या वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध, जो उत्पाद वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं, जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग हो, जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग पर प्रदर्शन उपभोक्ताओं को गुमराह करता हो, हालांकि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज और मिक्स फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक, या रखरखाू द्वारा अंतिम नियम जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत आदेश का पालन सभी संबंधित प्राधिकारियों और खाद्य कारोबार संचालकों को करना अनिवार्य होगा।

रेल परिवार से रायपुर मंडल के 17 सदस्य हुए सेवानिवृत्त

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत रेल परिवार के 17 सदस्य जुलाई 2026 में अपनी गौरवशाली रेल सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सामान्य सेवानिवृत्त हुए। इस समारोह में मंडल रेल प्रबंधक (दयानंद), सहायक कार्मिक अधिकारी (इन्द्रजीत कुमार सिन्हा), सेवानिवृत्त कर्मी एवं उनके परिजन, कल्याण निरीक्षक तथा बंदोबस्त अनुभाग के कर्मचारी एवं सभी विभागों से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। मंडल के सेवानिवृत्त होने वाले 17 रेलकर्मियों में 2 राजपत्रित अधिकारी जिसमे से एक विद्युत विभाग एवं एक इंजीनियरिंग विभाग से हैं इसके अतिरिक्त यांत्रिक विभाग से 03, इंजीनियरिंग विभाग से 03, परिचालन विभाग से 2, विद्युत् विभाग से 4 एवं वाणिज्य विभाग से 2 एवं सिग्नल और टेलिकॉम विभाग का 01 कर्मचारी शामिल है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का समस्त भुगतान प्रमाण-पत्र दिया गया। ई-पेमेंट के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुल राशि रुपये 74,68,7327/- का भुगतान किया गया।

ई-रिवशा और ऑटो पंजीयन अभियान 10 अगस्त तक बढ़ा

रायपुर। राजधानी रायपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन अभियान को जर्नहित में 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब वाहन चालक और मालिक 1 अगस्त 2026 से 10 अगस्त 2026 तक अपने ई-

17 Years of Progress with Purpose कार्यक्रम आयोजित

सीएससी डिजिटल क्रांति के वास्तविक सूत्रधार: वित्त मंत्री

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी आज रायपुर में कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा आयोजित 17 Years of Progress with Purpose कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीएससी संचालकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा डिजिटल इंडिया अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में उनके योगदान को सराहना की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई है। आज भारत डिजिटल लेन-देन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने प्रदेश के 38 हजार पंजीकृत सीएससी

संचालकों और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ नागरिकों को सरकारी सेवाएँ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएससी ने वास्तविक अर्थों में सिंगल विंडो सिस्टम को चरितार्थ किया है, जहाँ एक ही स्थान पर राजस्व, श्रम, बिजली, आयुष्मान, बैंकिंग सहित

अनेक सेवाएँ आम नागरिकों को मिल रही हैं।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, तब कई लोगों ने इसकी सफलता पर

सवाल उठाए थे। लेकिन आज भारत डिजिटल भुगतान, यूपीआई और जनसेवा के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। गाँवों तक डिजिटल सेवाओं की पहुँच ने डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि विकास का लाभ

समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाया है। इसी से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 तैयार किया है, जिससे विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य हासिल किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है। आज महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजनाओं की राशि बिना किसी कटौती के सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुँच रही है। इसमें सीएससी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बिजली के दाम कम करने तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस करेगी आंदोलन: वैज

रायपुर। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिजली के दाम की बढ़ोतरी वापस लेने तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने एवं 400 यूनिट तक बिजली बिल हॉफ योजना को फिर से शुरू करने के लिए कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है।

1 अगस्त को सभी जिलों में पत्रकार वार्ता लेकर बिजली के दाम बढ़ोतरी का विरोध किया जायेगा तथा बिजली के बढ़े दाम वापस लिये जाने की मांग की जायेगी। 2 अगस्त से कांग्रेस के कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर के खिलाफ घर-घर से आवेदन भरवा कर स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करेंगे

भरवायेंगे, बिजली के दाम बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग दो महिने तक करेंगे। दो माह पश्चात जिलों में भरवाये गये फार्म को लेकर प्रदेश भर में हम जिले के बिजली दफतर का घेराव करेंगे एवं एकत्रित आवेदन जमा करावेंगे, पावती लेंगे। सभी जिलों में फार्म भरवाने तथा जिले के बिजली दफतरों के घेराव के बाद प्राप्त पावती को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि बिजली मंत्री भी

है उनके निवास का घेराव करेंगे। जनता के द्वारा बिजली के दाम बढ़ाने में विरोध पत्र विरोध पत्र बिजली के दाम बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग दो महिने तक करेंगे। दो माह पश्चात जिलों में भरवाये गये फार्म को लेकर प्रदेश भर में हम जिले के बिजली दफतर का घेराव करेंगे एवं एकत्रित आवेदन जमा करावेंगे, पावती लेंगे। सभी जिलों में फार्म भरवाने तथा जिले के बिजली दफतरों के घेराव के बाद प्राप्त पावती को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि बिजली मंत्री भी

आर.एन.आई.रजि. क्र. CMHMHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.